साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Mob: +91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 15 अंक 10 प्रति सोमवार इंदौर, 05 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2020 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

चीनी जिनपिंग और भारतीय मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए

सीमा पर युद्ध लड़वा सैनिकों को मरवा रहे चीन और भारत

भूख व बेरोजगारी से परेशान जनता का ध्यान हटाने, बांटने,अपनी बहादुरी दिखाने, बताने 24 घंटे टीवी पर चिल्लाने, प्रसार माध्यमों, समाचार पत्रों को ध्यान बांटने भारत चीन सीमा पर युध्द का खेल चल रहा है।

दोनों देश की जनता को युध्दोन्माद में उलझा कर अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके। भारत में चीन के सामानों पर ज्ञान बांटने वालों मंद और गागरौनी बुद्धि के तोतों यह मोदी और जिनपिंग की नूरा कुश्ती में बेचारे सैनिकों को शहीद करवाया जा रहा है। सच

यह है कि दोनों ही अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता और देश के प्रसार माध्यमों का ध्यान परिवर्तित करने के लिए यह युद्ध लड़वा रहे हैं। दोनों ही हरामखोर जालसाज सूकरों मोदी और जिनपिंग थोड़े ही युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध तो सैनिक लड़ रहे हैं। ना दोनों के। यह तो बस सत्ता में बैठकर जनता को भ्रमित करने अपनी नाकामियों को छुपाने प्रचार माध्यमों को शिगूफा देने का कार्य कर रहे हैं। यह सब कुछ तो सितंबर की चीनी जिनपिंग की भारत यात्रा में ही खुसर पुसर हो चुकी थी! दोनों गल बहियां डालकर बैठे हुए थे। सामान आयात की छूट कौन देता है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय ही छूट देता है। ना। यदि सचमुच युद्ध करना होता। तो युद्ध के पहले दूतावास खाली करवाए जाते हैं। सारे अपने नागरिकों को बुलाया जाता है। एक दूसरे के देशों में, व्यवसाय, सारे काम धंधे बंद किए जाते हैं जो एक दूसरे के देशों में चल रहे हैं चीनी फैक्ट्रियां भारत में काम कर रही हैं और भारत के पूंजी पतियों की अनेकों फैक्ट्रियां चीन में चल रही है। स्वाभाविक है, यह सब कुछ नहीं हुआ। मोदी जाहिल गवार व मूर्ख है, पर चीनी जिनपिंग महा धूर्त और शातिर बुद्धि का, उसको मालूम है कि दुनिया के सारे कचरे माल को जो दुनिया में समय बाधित,खराब, बेकार और बकवास समझा जाता है।

(शेष पेज 2 पर)

■ दुनिया की हर लोकतांत्रिक सरकारों में बना

1965 के बाद बना हर कानून बहुराष्ट्रीय कंपनियों व पूंजीपतियों का

बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश की सरकारों और दुनिया के मीडिया को चलाती हैं

दुनिया की जालसाज बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसमें वॉलमार्ट का वारेन वफेट, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट, अमेजॉन का जेन बेजोफ, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, चीनी अमेजॉन, भारत का रिलायंस का मुकेश अंबानी जैसे महा धूर्त पाखंडी और जालसाज लोग अपने मोटे लाभ के लिए मोटा लाखों-करोड़ों में धन खर्च कर पहले कानून बनवाते हैं। जैसी भारत में 1965 के बाद बना हर कानून बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बनवाया हुआ था। अंतिम सबसे खतरनाक देश के 35 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने के लिए बनवाया गया कानून खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 मैं अकेले वारेन बुफेट ने भारत में 37500 करोड डॉलर खर्च किए थे इस कानून को बनवाने में बदले में उद्देश था किसानों के सारे खेतों पर कब्जा कर सारी फसलों को अपने मनमानी तरीके से अपनी मनमानी कीमतों पर खरीद कर अपने वॉलमार्ट के शॉपिंग मॉल के माध्यम से पैकिंग कर अपनी मनमानी कीमतों पर बैचना। इसमें टाटा बिरला अदानी आईटीसी हिंदुस्तान या युनिलीवर मैक डोनाल्ड, व अन्य कंपनियों ने भी पैसा खर्च किया था जो कुल लगभग 10लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा था। ताकि दुनिया के सारे छोटे व्यवसायियों उद्योगों रिटेल शॉप्स को खत्म कर सब पर इन शॉपिंग माल के जालसाज चांडाल सूअरों का कब्जा हो जाए। और वे किसानों के खेत से सीधा माल खरीद कर अपने शॉपिंग मॉल में भरकर मनमानी लूट दुनिया में मचा सकें उसी का हिस्सा है।करोना वर्ल्ड वाइड।यही पूंजीपति हर लोकतांत्रिक दुनिया की सरकारों को चलाते हैं।वही सरकारें और बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश और दुनिया के मीडिया को छल, बल, दल से खरीदकर चलाती हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यवसाय बढ़ाने के लिए और मोटा लाभ कमाने के लिए, देश और दुनिया के देशों की जनता में बीमारी का भय फैलाकर 6 महीने तक घरों में बंद करवा देती है और उसकी आड़ में देश और दुनिया के सारे व्यवसाय को चौपट कर देती हैं।

(शेष पेज 11 पर)

6 साल में बिनाश पुरुष मोदी हर स्तर पर किया देश का विनाश

घोर पाखंडी जाहिल मोदी बंद करो देश व जनता की बर्बादी

बाप की जागीर नहीं देश विदेश की संस्थाएं जिन्हें पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय को गुलाम कर दो

पिछले 6 साल में मोदी भारतीय जनता पार्टी और राक्षस सेवा संघ के सभी वरिष्ठ नेताओं को ब्लैकमेल करके या तो उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और जिनको लेना मजबूरी थी जिनके दम पर जनता को भ्रमित करके तुमने सत्ता हथियाई उनको धीरे-धीरे बीमारी के बहाने यमलोक पहुंचा दिया ताकि तुम्हारी मनमानियां बदतमीजीयां और देश को बर्बाद करने की नीतियां रोकने वाला कोई ना हो।

सन 2014 के बाद से वैसे तो जुलाई-अगस्त 2013 से तुमने देश की सत्ता को हथियाने का जो षड्यंत्र रचा था उसके अंतर्गत देश के बड़े पूंजीपतियों को उनके बैंक ऋणों को माफ करने के बदले में क्यों धन लेकर देश और दुनिया के मीडिया प्रसार माध्यमों सोशल साइट्स को खरीद कर छल कपट से जनता को भ्रमित करने में सफल रहे। बरन देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाली और चलाने वाली भारतीय प्रशासनिक बनाम भारती प्रताणना सेवा के अधिकारियों को भी छल, बल, दल से खरीद कर जिस तरह से ईवीएम की जांलसाजियों से तुमने सत्ता हथियाई। यह तो स्पष्ट हो गया था कि तुम जैसे तुमने गुजरात बर्बाद किया और जांलसाजियों से हजारों करोड़ का हेर फेर और भ्रष्टाचार किया। उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से देश की सत्ता संभ ालने के बाद करोगे। यह सच 6 सालों में तुमने हर कदम कदम पर स्वयं ही उसकी प्रस्तुति देते हुए स्पष्ट कर दिया।

(शेष पेज 8 पर)

भारत को दुनिया का उत्पादन केंद्र बनाओ, चीन की कोरोना की बर्बादी में

प्रवृति ने और उसकी कार्यप्रणाली प्राकृतिक एवं स्वचालित है। यहां हर अति का अंत होता है। वैसे ही चीन में कोरोना वायरस ने पिछले 40-50 साल से फैली हुई और चल रही चीन की व्यापार व्यवसाय हड़पो नीति, बर्बाद करो नीति, दुनिया में भरपूर हर माल का सस्ता निर्यात करो नीति ने चीन की सारी हेकड़ी, सारी होशियारी दुनिया पर कब्जा करने का मंसूबा कोरोना के बहाने सब का अंत कर दिया।

पूरी दुनिया में अपने सस्ते माल के कारण करोड़ों उद्योग धंधे बंद करने के साथ अरबों लोगों को बेरोजगार बना दिया था। हडपो नीतियों से उसकी सीमा से सटे हुए देशों जिसमें भारत, म्यांमार, उत्तरी-दक्षिणी कोरिया, ताइवान जापान, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांगलादेश, सब को परेशान कर रखा था। सारी चालाकियां कोरोना ने ध्वस्त कर दी।

प्रकृति में किसी के नुकसान से किसी का फायदा होता है। चीन में ज्यादा आबादी का भरपूर फायदा उठाते हुए चीन की कम्युनिस्ट सरकार जिसे उसकी आबादी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं लगती, ने अपने यहां अंतरराष्ट्रीय सभी

श्रम कानूनों को समाप्त करके अपनी जनता को निचोड़ने के लिए दुनिया भर में फैले उत्पादन व्यवसाय जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर, खिलौने, वस्त्र, औषधियों, चिकित्सीय उपकरण, सस्ते कॉस्मेटिक, स्वचालित वाहनों व उसके कल पुर्जों, भारी मशीनों, से लेकर रक्षा सामग्री बंदूक से लेकर तोप टैंक और युद्धक विमानों तक के साथ उसके गोला बारूद, मिसाईलों, राडार उपकरण तक छोटे बड़े हजारों तरह के सामनों का उत्पादन करने लगा।उस के उत्पादन के लिए दुनिया भर के उत्पादकों को सस्ते श्रम सस्ती जमीने मुफ्त बिजली-पानी आदि की घोषणा कर का दुनिया का सबसे सस्ते और स्तरहीन, अविश्वसनीय हर प्रकार के माल का बड़ा उत्पादक देश बन गया। इसके कारण अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल, ब्रिटेन आदि के केवल उत्पादन चौपट करने से भी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। दूसरी तरफ भारत की 140 करोड़ की आबादी उसके लिए दुनिया भर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। परंतु कोरोना वायरस ने उसकी उत्पादन क्षमता पर असर डालने के साथ में दुनिया के अधिकांश देशों ने भारत और अमेरिका के साथ व्यापार की गति को शिथिल कर दिया।

अब भारत की मोदी सरकार के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जबकि वह अपने देश में चीन से आयात होने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सामानों यथा कंप्यूटर मोबाइल उसके सभी सामान यथा हार्डडिस्क से लेकर मेमोरी कार्ड तक के हजारों किस्म के उत्पादन,

(शेष पेज 13 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी जालसाजी भरी मशीन

मैं सन् में 2006 चुनाव से लगातार कह रहा हूं की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी जालसाजी भरी मशीन है। जैसा कि हवाई जहाज उड़ाने के प्रशिक्षण लेते समय वैमानिकी से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन पर मैंने सबसे महत्वपूर्ण एक बात पढ़ी थी, की मनुष्य ने मशीनों को बनाया है उसको जिस प्रकार से बनाकर चलाने के लिए निर्देशित करेंगे वह वैसे ही चलेगी। चाहे हवाई जहाज हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, घर का मिक्सर या टीवी कूलर, कंप्यूटर, वह वैसे ही चलेंगे। मनुष्य उसके चलाने में गलती कर सकता है। मशीन चलने में गलती नहीं करती। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपने जैसे उस को बनाया, निर्देशित किया है। वह वैसे ही काम करेगी उसमें जीपीआरएस, जीपीएस, डब्ल्यू एल एल, रिमोट, ब्लूटूथ आदि सभी दूर निर्देशों का पालन करने के लिए बनाई मशीन है। और उसमें जैसी कमांड भरी जाएगी जैसे कि हर 5 वोट में 3 वोट बीजेपी के वह आप कैसे भी वोट डालें प्रिंटर कुछ भी प्रिंट निकाले परंतु दिए हुए निर्देशों या दिल्ली में बैठकर हर मशीन के कोड के आधार पर मोबाइल की तरह उसकी संख्याओं को आप आसानी से प्रबंधित कर लेते हैं। वह लाख स्ट्रांग रूम में रखी जाए या बैंक की बड़ी तिजोरी के अंदर, बाहर आते ही काउंटिंग से पहले भी उसको आप कमांड देकर अपने हिसाब से वोट संख्या निकाल सकते हैं। और यह काम कलेक्टर बखूबी तरीके से अंजाम देता है सब को दिखाता है। उससे क्या होता है? 18 अप्रैल 14 को शाम 4:30 बजे एक टेलीफोन इंदौर जिला कलेक्टर ऑफिस से आया सर मशीन लॉक कर रहे हैं। आप आ जाइए। तो मैंने उसको फोन पर ही बोला मैंने कहा भैया मैंने एक ?10000 में मोबाइल खरीदा था तीन भाई 5 इंच का वह मोबाइल 3 साल से सीने से लगा कर घूम रहा हूं मुझे आज तक नही मालूम उसमें क्या कैसे कितने फंक्शन हैं? तो मैंने कहा तुम्हारी वह डेढ़ फुट बाई6 इंच की मशीन मैं तुमने क्या किया फिट कर रखा है। w.l.l. है, वाईफाई है, जीपीआरएस है, जीपीएस है, ब्लूटूथ, रिमोट, ब्लूरे कहां कैसे क्या फिट कर रखे हैं। मैं तो इस बारे में भी अनपढ़ हूं। हार्डवेयर इंजीनियर भी नहीं हूं जो मैं उसमें जांच लूं कि कहां क्या कैसे फिट करके कैसे दूर बैठकर चलाई जा सकती उसका कोड क्या है मुझे क्या मालूम आप तो लॉक कर लो जैसे आपको लॉक करना है। मेरे आने का कोई फायदा नहीं। तत्काल पलट के कर्मचारी बोला, सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। पर आपसे आज बातचीत करके मुझे लगा सचमुच आप बहुत सही सटीक न केवल लिखते हैं बल्कि सही और सटीक जवाब देते भी हैं। मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। मेरी बातों को छिछोर बुद्धि मजाक में उड़ाते हैं। पर डबरा की बिनां विधायकी मंत्री इमरती देवी ने वह सच सीधे स्वीकार करके स्पष्ट कर दिया कि सारा खेल जिले के घोर जालसाज, भ्रष्ट, कलेक्टर ही करते हैं। बस स्तर का कलेक्सन मिलना चाहिये। अब आप कहेंगे की फिर तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार क्यों बन गई? तो आपको बता दें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तीनों मुख्यमंत्री तीन तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। और केंद्र का निर्देश था। कि यह पुनः मुख्यमंत्री ना बने। वरना उनके हाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे इसलिए इन्हें हरा दो। इसलिए उन्हें हराया गया था ताकि उनके हौसले बुलंद होते होतै तक मोदी की कुर्सी तक ना पहुंचे और अरमान ठंडे कर दिए जाएं। दूसरी तरफ तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक की अत्यधिक अग्रिम स्तर पर बैठे राष्ट्रों अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी जापान कनाडा फ्रांस चीन रूस मैं आखिर ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होते। आखिर भारत में ईवीएम से ही चुनाव क्यों करवाए जाते हैं यह बकवास बंद कीजिए धन ज्यादा खर्च होता है तो धन नेताओं तुम्हारे बाप यहां रख छोड़कर नहीं गए थे। देश का धन देश में खर्च होगा। खर्चा बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जनता का पैसा है। तुम लाखों करोड़ लूट कर खा जाते हो लोगों के कर्ज माफ कर देते हो। तो कागज के मतपत्र से चुनाव कराने में क्या तकलीफ आती है और क्यों अपनी होशियारी दिखाते हो। ताकि आसानी से जालसाजी से चुनाव जीत सको।

इंदौर शहर वासियों को सारा सरकारी आतंक सहने झेलने के लिए नंबर वन का पुरस्कार

इंदौर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी सबसे ज्यादा सभी प्रकार के कर देने वालों में पूरे प्रदेश में अग्रणी होने के उपरांत भी पूरे प्रदेश में सबसे घोर भ्रष्ट जालसाज अधिकारी कलेक्टर कमिश्नर पुलिस अधिकारी जनता को लूटने परेशान करने और उनका शोषण करने के लिए बैठा ले जाते हैं।

पहले वर्षों तक हर सरकारी कर्मचारी यहां तक कि नगर निगम के बेलदार जमादार से लेकर जिले का कलेक्टर कमिश्नर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबको अपनी लूट, भ्रष्टाचार, जालसाजियों, के लिये आम गरीब नागरिकों के साथ अपनी सभी जालसाजियों और भ्रष्टाचार छुपाने के और इन सब से ध्यान हटाने भय पैदा करने लिए उनकी लूट, कूट, मारपीट, अपमान अकाल मृत्यु के लिए इंदौर के शहर वासियों का भारी तिरस्कार, और फिर अपनी लूट भ्रष्टाचार पाखंड जालसाजियों पर भी जनता के बाहर ना आने सब कुछ सहने झेलने के लिए नंबर वन का पुरस्कार।

धन्य हो इंदौर वासियों 6 महीने से भारी घोर पीड़ा अपमान लूट पाखंड और जालसाजीयों को झेलने के बाद में भी कोई प्रतिरोध कोई प्रदर्शन नहीं करने का पुरस्कार है पूरे देश में हर जगह बीआरटीएस असफल रहा और उखाड़ दिया गया

दिल्ली अहमदाबाद वह अन्य कई शहरों में परंतु इंदौर की जनता को बीआरटीएस को झेलते हुए 10-12 साल गुजर जाने के बाद में भी कोई प्रतिरोध नहीं। 6 महीने से सभी नेताओं मंत्रियों नगर निगम के बिल्डरों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस का घोर तांडव चलता रहा। वसूली और पाखंड के लिए सैकड़ों लोगों को महामारी के पाखंड की आड़ में मौत के घाट उतार दिया गया। अरविंदो और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज द्वारा जिनके मालिक विनोद भंडारी और सुरेश भदोरिया व्यापम कांड में गहरे तक लिप्त होने के कारण विनोद भंडारी ने साडे 3 साल जेल काटी और सुरेश भदोरिया पैसे बांट कर फरारी काटता रहा। वहां मौत का तांडव चल रहा है। मोटी बसूली कलेक्टर कमिश्नर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को जो छोटी मोटी दूसरी बीमारियों को शिकार थे। को जानबूझकर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी घातक दवाई देकर जिनको 50 साल से ऊपर के लोगों को जो रक्तचाप मधुमेह व अन्य बीमारी के शिकार होते हैं। देते हुए उनकी लिवर किडनी और हृदय फेल कर देता है। अकाल मौत का शिकार बनाए जा रहे हैं। गोकुलदास में तो 9 लोगों को इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उनको मरीजों को खाली करवाकर सफाई करनी थी। इतने सारे कांडों को झेलने के बाद में भी इंदौर की जनता चुप है। इसलिए उसके घावों पर मरहम लगाने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर उसे नंबर वन का पुरस्कार दिया गया। और सारी भेड़ों की फौज, सारे घावों के दर्द छुपाते हुए जीवित भेड़े खुशी से पूछ उठाकर नाच रही हैं। यही तो झूठ प्रशासन नेता पुलिस मंत्री और मुख्यमंत्री चाहते थे कि पुरस्कार देकर उनके घावों पर मरहम लगा दो। कोई कुछ नहीं बोला और मूर्ख नंबर वन पाकर खुश हो गए जबकि सड़कों पर 1 घंटे पानी गिर जाए झमाझम बारिश में पूरा शहर तालाब बन जाता है। यह है सफाई की सच्चाई। जो पोस् कालोनी साकेत, कंचन बाग, साउथ तुकोगंज, न्यू पलासिया में कचरा डंपिंग स्टेशन बनाने के बाद पूरा न्यू पलासिया जो पोस कॉलोनी है। अब बदबू 2-3वर्ग किमी में सांस लेना मुश्किल कर चुकी है।

वही हाल तिलक नगर में भी हुआ वही हाल दक्षिणी तुकोगंज में भी हुआ और यही हाल पूरे इंदौर का है। जहां जहां कचरा डंपिंग स्टेशन मोटी कमाई के लिए बनाए गए यथार्थ में 24 घंटे 12 मास बदबू का अड्डा बन कर वहां के पोस कॉलोनी वालों का जीना दूभर किए हुए हैं। यह है इंदौर की सफाई की सच्चाई का एक छोटा सा अंश। पिछले 20 सालों में हजारों करोड़ नालियों को खोदने बनाने, नई पाइप लाइन बिछाने मैं नेता अधिकारी हजम कर गए और मूर्ख जनता अपनी कमाई में उलझी रही कोई कुछ नहीं बोला। और पानी यथावत आधे घंटे पानी गिर जाता है। तो सड़कों को तालाब में मोहल्लों को कीचड़ में बदल देता है। पर मीडिया के मृतात्माओं के लालची भेड़ियों जिसमें भास्कर पत्रिका नई दुनिया व अन्य दैनिक समाचार पत्रों को मुंह भर के विज्ञापन के साथ पत्रकारों को भी महीना मिलता है। सब टुकड़खोर चुप रहते हैं सच नहीं छापते। कहानी सच्चाई की बाकी है।

सीमा पर युद्ध लड़वा सैनिकों को मरवा रहे चीन और भारत

पेज 1 का शेष

वह भारत में आसानी से बिक जाता है। बिना किसी को परेशानी और काट छांट मीन मेख निकालें। कोई कानूनी उलझन नहीं, जांच, झमेला नहीं व हल्ला नहीं। चाहे वह चप्पे-चप्पे पर अपने मोबाइल फोनों से लेकर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से लेकर प्रोसेसर तक भारत में उसी का उपयोग होता है।

सबसे वह जासूसी करता है और चप्पे-चप्पे की खबर रखता है। भारत से बढ़िया कोई बेहतर बाजार नहीं मिल सकता। जो बात चीन के बारे में मैं समय माया समाचार पत्र में छाप रहा हूं, लगातार की हमारे यहां हमारे संचार माध्यमों से जिसमें हमारे यहां की संचार कंपनियां चाहे सरकारी बीएसएनएल, एमटीएनएल, विदेश संचार निगम लि के साथ अंबानी कि रिलायंस, टाटा की डोकोमो, बिरला की आइडिया, वोडाफोन व अन्य जो अपने संचार उपकरणों का प्रयोग कर रही हैं। सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण चीन के ही उपयोग किए जा रहे हैं।

जो हमारे देश में नागरिकों से लेकर सभी वीवीआईपी की भी बातों की, आने जाने की, खाने-पीने, उठने बैठने, बातचीत का सारा डाटा रिकॉर्ड कर रही है। जिसकी सच्चाई सामने आ चुकी है।

और चीन आज से नहीं, पिछले 40 सालों से देश के अंदर गांव के सरपंच सचिव से लेकर पत्रकारों समाचार पत्रों विधायकों पार्षदों नेताओं मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की जासूसी में लगा हुआ है यह सब जानने के बाद में भी आज तक भारत सरकार ने खासतौर से मोदी ने 6 साल में इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया और ना ही अपने सारे संचार माध्यमों की कंपनियों निजी व सरकारी को कोई भी पत्र यह दिशा निर्देश नहीं दिए इसी कारण वह जानबूझकर अपने उपकरणों को देश के अंदर सस्ते में बेचकर ना केवल देश में वरन दुनिया के हर देश में आसानी से वहां के चप्पे-चप्पे की हर व्यक्ति की अपनी गोपनीय जानकारियों को सरेआम आसनी से इकट्ठाकर जासूसी कर रहा है। यदि वह युद्ध लड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। जितना भुगतान चीनी आयात के बदले में भारत से प्राप्त होता है। उतना दुनिया के किसी भी देश से प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह युद्ध नहीं लड़ेगा। यह सब कुछ चल रहा है यह जनता को अपने अंधभक्त मूर्खों को अपनी बहादुरी दिखाने और मोदी की 6 साल की नाकामियों को छुपाने, क्योंकि कोरोना की कोई बीमारी भारत में नहीं थी।

जितने मारे गए अस्पतालों में ले जा ले जा कर जानबूझकर मारे जा रहे हैं और यह ठीक करके भेजा जा रहा है यथार्थ माने तो कोरोना नाम की कोई संक्रमक बीमारी वैसे भी नहीं थी। जिसका वीडियो मैंने इसमें पूर्व में भेजा था जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की महिला प्रवक्ता ने स्वयं कहा यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। इसके विपरीत अकेले इंदौर में 15 से 20 करोड़ रुपए के हाथ साफ करने के सैनिटाइजर और उसकी मशीनें, पंप वाली बोतलें बिक गई। अकेले इंदौर में ही 6महीने में 2 करोड़ से ज्यादा मास्क बिक चुके हैं। ताप व आक्सी मीटर की डिजीटल मशीनें का भी रु.2 अरब से ज्यादा का कारोबार हुआ। जो सब चीन की थी तो भी बीमारी की आड़ में फायदा तो चीन का ही हुआ। फिर आखिर साडे 27 टन यह सारी सामग्रियां जो महामारी से संबंधित थी मोदी ने चीन से ही क्यों खरीद कर मंगवाई। वह स्वयं चीन का फायदा करवा रहा है? देश के उद्योग धंधे को चौपट कर दिया है 6 साल में उसने साफ-सफाई नोटबंदी जीएसटी में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय पूंजी पतियों के पहले और बाद में चीन की कंपनियों का ही हुआ ना।

दूसरी तरफ जांच करने की किट, पीपीई किट, 500 करोड़ से ज्यादा मास्क, तापमान नापने की 10करोड़ से ज्यादा हाथ की मशीन, वह सब चीन की ही है। और इस पर हो रहे जब मनुष्य का तापमान 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है।

तो वह 93, 94 तापमान दिखाने पर भी तापमान लेने वालों को खुश तो कर रहा है। यह किसी मूर्ख को समझ में नहीं आ रहा। अर्थात वह तापमान नापने वाली हैंड गन ही खराब है। यह नौटंकी किसी को समझ में नहीं आ रही। अकेले इंदौर में वह सो रु 200/- की मशीन रु 2000/- में लगभग 20000 सरकारी व निजी कार्यालयों, दुकानों, उद्योगों विभागों में ही खरीद ली गई है। तो भी फायदा चीन हीं का हो रहा है।

यह अंध भक्तों को समझ में नहीं आएगा। सत्ता और पूंजी पतियों की रखैल वेश्या मीडिया और 20 करोड़ भूखेरे मिडिया में 24घंटो चल रही विपणन एजेंसियों के झूठे फरेब के बांटे जा रहे पाखंड पूर्ण प्रसार में पगे छिछोर बुद्धि के घोरज्ञानी अंधभक्तों को हुआ हुआ करने के लिये कोई न कोई शिगूफा चाहिए। चाहे वह जाहिल गवार इन कटोरा हाथ में देकर चौराहे पर खड़े कर इनको गोबर ही क्यों ना दे पर उसे यह उसे भी मिठाई समझकर खाएंगे और चिल्लाएंगे।

दो गिध्द ही काफी हैं, इंदौर के व्यावसायिक गुलिस्तां को बर्बाद करने में

प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यवसायिक की राजधानी को बर्बाद करने में दो ही गिध्द काफी हैं। पहला शिवराज का वसूली वाला दल्ला मनीष सिंह कलेक्टर और दूसरा भेड़िया वह भूमाफिया झुंड पार्टी का दल्ला सांसद शंकर लालवानी, सह सिंधी व्यापारी जिसने नगर बंदी के उच्चतम नौटंकी वाले काल में अप्रैल और मई में किशोर वाधवानी का गुटका बिकवाने में मनीष सिंह के बीच दल्ले की भूमिका निभाकर लगभग 7000 करोड का असली नकली गुटखा सिगरेटों को पूरे देश में बिकबाने में महती भूमिका अदा की। और अभी भी मोटी कमाई डॉक्टरों नर्सिंग होम चिकित्सालयों में आमजन को सर्दी खांसी जुकाम की बीमारी की आड़ में घरों से उठाकर अस्पतालों में भर्ती करवा कर प्रति मरीज की चिकित्सा में 20-80, 60-40 के अनुपात में आबंटन व अकाल मौतों के चलते मरीजों से वसूली और सरकारी आवंटन में से मोटे कमीशन की वसूली का खेल करते हुए तांडव को बढ़ाने और शहर में दहशत फैलाने में शंकर लालवानी व मीडिया का भरपूर उपयोग कर शहर के पूरे व्यवसाय और बाजारों को बंद करवाने में अपनी भूमिका अदा करता रहा। बेशक इंदौर के व्यवसाय को बचाने बाजार खुलवाने की कोशिश लगातार चलती रही। परंतु शंकर लालवानी ने मई जून-जुलाई में बाजार खुलवाने मैं मोटी वसूली करने में भी कलेक्टर के साथ मोटा खेल किया।

बस एक घूंट जालसाज वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह जो पूर्व में इंदौर में एडीएम और एसडीम भी रह चुका है एडीएम रहते हुए सन 2002 मई 16 सॉल्वेंट प्लांट के नाम से फर्जी लाइसेंस बनवा कर खूब फर्नेस ऑयल को मंगवा कर पेट्रोल पंपों में एनी की संख्या में आपूर्ति कर बिकवा जाता था जो पेट्रोल की कीमत का एक तिहाई होता है जिसकी भनक तत्कालीन कलेक्टर सुलेमान को लग गई थी। फिर पटवारी तहसीलदार एडीएम एसडीएम ऑफ कलेक्टर का सबसे बड़ा खेल होता है जमीनों का, राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक से लेकर पटवारी, से लेकर नायब व तहसीलदार, सहायक, उप, जिलाधीश, आयुक्तों का जो मोटा पैसा खाकर जानबूझकर भू माफियाओं कॉलोनी माफियाओं खनन माफियाओं को चरनोई की, नजूल, सरकारी, ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ, वन भूमि शासकीय विभागों जिसमें सरकारी विद्यालयों, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन की तालाबों की, नहरों की, उनके जल संग्रहण क्षेत्र की भूमि पर, नगर निगम पालिकाओं, वन भूमि के साथ व्यक्तिगत भूस्वामी की जमीनों पर जानबूझकर फैक्ट्री प्लांट कालोनियां अनुमति पट्टे बांटने में आज्ञा और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में करोड़ों रुपए हजम कर रजिस्ट्रीयां करवा कर यह हरामखोर जलसा जो का झुंड निकल लेता है और बाद में भूस्वामी वह अति गुणकारी सालों तक न्यायालय में मुकदमे लड़ा कर रहे हैं और वकीलों का फायदा करवाते हुए जिला न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक विवादों को जन्म देते हैं यह इनका प्रिय डकैती का खेल होने के साथ यह 400 कानूनों में अपनी इच्छा अनुसार मोटर धन खाकर निर्णय देते रहते हैं। यही कारण था कि भरे लॉकडाउन में 28 मार्च को मोटा धन क्योंकि पहले भी शिवराज की रसोई तक पहुंच रहा था। इसलिए इस प्रमोटी कलेक्टर के रूप में इंदौर में पदस्थ कर दिया यह उसी मोती सिंह का बेटा है जिस मोती सिंह ने करोड़ों रुपए लेकर 4 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन के भारत आने पर और विवाद खड़ा होने पर चुपचाप अपनी जीप में डालकर उसे हवाई अड्डे छोड़ कर आ गया था उसका बेटा 36 साल

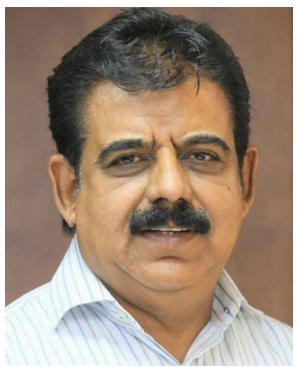

बाद अपने बाप के इतिहास को दोहराते हुए, पिछले 6 महीने से इंदौर की जनता को मारा कुटी करने से लेकर फुटपाथ पर, ठेलो पर सब्जी फल फ्रूट अन्य सामग्री बेचने वालों सब्जी फल फ्रूट छीन कर नगर निगम के कर्मचारी पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों ने मार्च-अप्रैल मई-जून तक भारी तांडव करके बारी करोड़ों रुपए वसूली की इसके बाद भी व्यवसाय चौपट करने से लेकर और गरीब ठेले वालों पर बादलों की धीरे छोड़े गए सब्जी लूट कर बैठी खाई गई और बाटी गई, गरीबों, विधवाओं, असहाय बुजुर्गों आदि के लिए आए हुए राशन पानी तेज दूध जाले आती जनता को बांटने की अपेक्षा केवल 20 से 30% बांटा गया और 70% उस सामग्री का धन इसी मनीष सिंह के सरंक्षण में मनीष सिंह के प्रशासनिक अधिकारियों खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अधिकारियों, निगम वह पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों, सांसद लालवानी से लेकर सभी पार्टी के नेताओं, विधायकों, पार्षदों, महापौर तक सबने हजम कर लिया उसकी कोई जांच नहीं किसको कितना बाटा। कोई हिसाब नहीं अंधा बांटे रेवड़ी सारे नेता प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस कर्मियों निगम अधिकारियों कर्मचारियों ने खुलकर जनता को राशन आपूर्ति करने सफाई के नाम पर वेरी कटिंग के नाम पर लाइटिंग व्यवस्था खाने-पीने आदि के ठेकों के नाम पर अरबों रुपए का भ्रष्टाचार इंदौर में हुआ जिसमें मोटा शेयर विधायकों सांसदों से लेकर सभी संबंधित विभागीय विभाग के अधिकारियों ने मोटी वसूली की उस वसूली का कुछ हिस्सा स्वभाविक था जिस आका ने अचानक 28 मार्च को इंदौर का कब घोषित कलेक्टर घोषित कर वहां पदस्थ किया था मोटा हिस्सा भेजा गया इसीलिए लंकेश शिवराज ने मनीष सिंह को इंदौर में बैठाया।

उसके खिलाफ एकमात्र नेता कैलाश विजयवर्गीय ही अपने बोल वचनों से बचाने की कोशिश करता रहा। पर उसके पीछे शिवराज और शंकर लालवानी की रणनीति उसको दबाने की बनी हुई चल रही है।

फिर स्वास्थ्य विभाग के सफेद अप्रैन के गिद्धों मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर सभी निजी व सरकारी डॉक्टर जिनके बड़े अस्पताल हैं। अपनी मोटी लूट के लिए जानबूझकर जब कोई निश्चित वायरस ही नहीं है, इलाज की पद्धति और औषधियां ही नहीं है। तो फिर किस आधार पर नकरात्मक सकरात्मक दिखाने के परिणामों जबकि पूर्ण आधुनिक प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में उपकरण, मशीनें, सामग्री टेस्टिंग किट परीक्षण करने वाले कर्मचारी डॉक्टर पूर्ण रूप से उच्च शिक्षित एमएससी पैथोलॉजी और एमडी पैथोलॉजी ही नहीं है तो कैसी कोविड-19 की नकरात्मक, सकारात्मक रिपोर्ट और उस पर दी जाने वाली दवाइयां बदले में चंद घंटों में ही अचानक मौत और वह भी हृदयाघात किडनी, लीवर फैलियर आदि से हो रही है। पर अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चांडालों के इशारे पर 24 घंटे मोबाइलों टीवी समाचार पत्रों में दहशत बांटकर जिंदा और खुशदिल जनता जो सब के भले और सहयोग की कामना और कार्य करने वाले जनता के शहर को मुर्दों का शहर बनाने पर तुले हुए हैं।

बेशक इन के सहयोग में पूरा भेड़िया व भू माफिया झुंड पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज उसके सारे मंत्री जो अभी तक चुनाव नहीं जीत पाए 6 महीने में, उनके इशारे पर प्रशासनिक अमला नगर निगम में बैठी हुई उस की चेली प्रतिभा पाल, पुलिस अपनी मोटी कमाई के लिए न केवल इंदौर वरन पूरे प्रदेश और चांडाल गुजराती तेली मोदी प्रधानमंत्री देश को दहशत के साए में रखकर बर्बाद करने पर तुले हैं। 6 साल में उस गुजराती राक्षस ने देश को केवल दहशत और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया जिसमें यह सारे भ्रष्ट, जालसाज, लालची भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों ने जिन्होंने उसे ईवीएम की जालसाजी से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में दो बार अंधसहयोग दिया। पूरे देश को अपनी लूट वसूली के लिए बर्बाद करने पर तुले हुए हैं हरामखोर इसको जनता समझे दहशत में ना आए। अन्यथा गिध्दों का जन्म तो प्रकृति ने मुर्दों को नोंचने, साफ करने के लिए ही किया है। समझे। सुरक्षा सतर्कता और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।

इन सब का ख्याल रखते हुए जनता के हर वर्ग से विनम्र निवेदन है, कि आप भी अनाज खाते हो बुद्धि है, तो डर और दहशत से दूर रहकर, सावधानी और सुरक्षा के साथ अपने परिवार की अपने सहयोगी, सहकर्मचारियों की अपना अडोसी पड़ोसी गली मोहल्ले के साथ जनता की सुरक्षा रखते हुए खुलकर भरपूर व्यवसाय करें। लाकडाउन विकल्प नहीं है।

6 माह के महामारी के पाखंड की आड़ में लाकडाउन में लगभग ने चारों तरफ पूरे नगर प्रदेश देश और दुनिया में बहुराष्ट्रीय पूंजीपति कंपनियों वॉलमार्ट अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील के साथ भारत के अडानी अंबानी टाटा बिरला का व्यवसाय तो चारों तरफ हर क्षेत्र में बढ़ाया। जो कि छोटे मझोले उद्योगों व्यवसाय को खत्म करना और देश के 10 करोड़ से ज्यादा छोटे उद्योगों व्यवसायों को खत्म करना लोगों को बेरोजगार कर अपनी मोटी कमाई करना ही उनका पावन उद्देश्य था।

परंतु देश के आम 100 करोड़ और दुनिया के लगभग 500 करोड जनता की तबाही मचा दी।

सुरक्षा के साथ बिना भयभीत हुए अपना व्यवसाय धंधे रोजगार कर आपके साथ आपसे जुड़े लोगों की रोजी-रोटी चल सके। आप की अर्थव्यवस्था सूचारू हो, जनता की सुचारू हो उससे देश की अर्थव्यवस्था अपने आप सुचारू हो जाएगी। उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। आप मत समझिए कि आप फुटपाथ पर बैठे, ठेला चलाने वाले, छोटी दुकान चलाने वाले, छोटा उद्योग व्यवसाय चलाने वाले छोटे से व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी हैं। आप धरती पर प्रकृति द्वारा किसी विशेष काम के लिए पैदा किए गए हैं। अपना काम, व्यवसाय, धंधे करें। सावधानी से सुरक्षित रह कर और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सहयोग करें। अभी आपके लिए प्रभु का भेजा यह बंदा धरती पर है। जो आपकी, आप के हितों की, बच्चों की शिक्षा के लिए, मजदूरों के हितों के लिए हर कदम पर, आपके परिवार की हमारी युवा होती पीढ़ी की सब के सुरक्षित भविष्य के लिए, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस रूपी वसूली बाज कमीशन खोर चांडालों से सतत युद्ध लड़ रहा है।

80 करोड़ लोगों को मुफ्त आटा, मध्यम वर्गीय लोगो के घरों में रखे सोने और बैंको में रखे धन को लूटने की तैयारी

80 करोड़ लोगों को जैसा उस पाखंडी जाहिल पूंजी पतियों की रखैल मोदी ने बताया अगले 4 महीने तक मुफ्त आटा जो पूंजीपतियों के गोदामों में लटों और इल्लियों युक्त खराब हो चुका होगा। वैसे शास्त्रों में पिसे हुए आटे की केवल 8 दिन आयु होती है। पर आटा मिलें उस में कीड़े न पड़े उसमें हल्के कीटनाशकों डीडीटी व अन्य घातक रसायन मिलाती हैं। ताकि 3 माह तक उसमें कीड़े न पड़े। पहुंचाए जाता रहेगा। और 70 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर मध्यम और उच्च मध्यम वर्गीय उनके बाप अमेरिकी वालमार्ट, चीनी जोमेटो व स्वि ग्गी जिनसे लाखों करोड़ कमीशन हजम किया है। वालमार्ट, अंबानी, टाटा बिरला मित्तल के व अन्य के शापिंग माल्स से आनलाईन खरीदी कर इन भूखे भेड़ियों मंत्रियों, कलेक्टर कमिश्नर और पुलिस को मोटा कमीशन हर महीने पहुंचाते रहें। अर्थात रेलवे को पूरी तरह से तबाह कर आसानी से व अन्य सभी विद्युत, तेल, वित्तीय, सरकारी कंपनियों, विभागों व निजी फैक्टरीयों, मिलों उद्योगों को पूरी तरह से बर्बाद करने का षड़यंत्र चल रहा है। 75 करोड़ लोगों की बैंकों में जमा पूंजी, घरों में रखे संपत्तियों आभूषणों, सोने, जमीनें, मकान आदि को हज़म करने के लिये उच्च स्तरीय षडयंत्र को बेरोजगार कर कंगाल बनाने का खेल चल रहा है। उस गुजराती घोर निम्न मानसिकता मोदी की

निगाहें मध्यम वर्गीय लोगो के घरों में रखे सोने और बैंको में रखे धन को लूटने पर लगी हैं। बेशक अंधभक्त दूसरा विधवा विलाप करते हुए उस चांडाल मोदी की तारीफ में ही अपना जीवन धन्य समझते हैं। लगे रहना चाहिए कुछ ऐसे अंध भक्तों को जो विधवा प्रलाप करते हुए 6 साल में देश की हर तरह की तबाही देख कर भी गुणगान में स्वामी भक्त श्वानों की भांति पूंछ मटका रहे हैं। प्रिंट और दृश्य मिडिया के भडुवो मोदी की छल कपट पूर्ण भक्तों की फौज वैसे तो देशबंदी के पाखंड में व्याव सायिक विज्ञापनों के अभाव में काफी सिकुड़ चुकी है। कब तक दम भर के टिकी रहेगी? महामारी के देशबंदी के पाखंड में तन से, मन से, धन से कौन मरा? और पुलिस ने, प्रशासन ने, डाक्टरों ने किसको मारा? महामारी के पाखंड में अधिकांश मध्यम वर्गीय ने जन के साथ धन भी गंवाया और अपने ही अड़ोसी-पड़ोसी के रिश्तेंदारों के बीच अनावश्यक घृणा, उपहास और उपेक्षा के शिकार हुये।

वही हिंदुओं के छोटे व्यापारियों, उद्योगों, निजी नौकरी पेशा, निम्न और मध्य मध्यमवर्गीयों की ही बर्बादी और शोषण हुआ। जो मोदी के अंधभक्त टिड्डों की फौज थी। जो घोर भ्रमित अतिज्ञानी हैं।

जो मक्खियों को लोंग और कीचड़ को हलुवा बता प्रस्तुत करते हैं।गरीबों ने तो लाईन में या नेताओं की जी हजूरी कर मुफ्त का राशन सहायता प्राप्त कर ही ली और कर लेंगे। जो चुनाव के समय भी शराब के पौऐ लेकर वोट डालते हैं। 80करोड़ वोटर को मुफ्त राशन बांटकर मौत तो हिन्दू मध्यम वर्गीयो विधवा विलापी अंधभक्तों की ही होनी है।

फिर वही कहानी याद आती है। की कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी और जंगल के अंधभक्त वृक्ष इस से ही खुश थे कि उसके हत्थे में लगी लकड़ी तो हमारे जंगल की ही है। जब तक प्रभु प्रेरित कर, देश बचाने में उपयोग कर रहा है। तब तक जागृति लाने का प्रयास करना ही पड़ेगा।

साप्ताहिक समय माया

घोर पाखंडी जाहिल मोदी बंद करो देश व जनता की बर्बादी

पेज 1 का शेष

सत्ता संभालने के साथ ही मई 2014 से लगातार 14-15 से ही लगभग 98 देशों की यात्राएं जनता के लुटे हुए धन से करते हुए अपने खास मित्रों अदानी, अंबानी, टाटा, व अन्य जिनका अपने लाखों करोड़ का बैंकों से लिया हुआ कर्ज जो जनधन था उसको आपने अपने बाप की जागीर समझते हुए इंसेंटिव के रूप में माफ कर दिया। आखिर क्यों और जब जनता ने और मीडिया में इन सबके बारे में हल्ला मचा। तो आपने लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा कर झाड़ू पकड़ाते हुए, देश की बैंकों सार्वजनिक संपत्तियों, सार्वजनिक उद्योगों, उपक्रमों, बीमा कंपनियों, तेल कंपनियों, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयर इंडिया आदि को उन की आड़ में धीरे-धीरे सब को निपटाना शुरू कर दिया। वह अंबानी जो अपनी जांलसाजियों से जनता से धन लूटने के साथ ही, सरकारी संपत्तियों का उपयोग कर बर्बाद करने के नाम पर यहां तक की केजी बेसिन सिक्स के कुएं में से रुपए 11000 करोड़ से ज्यादा की गैस चोरी कर चुका था। 1970 के बाद से लगातार जनता का धन लूटने के लिए कदम कदम पर शेयर व डिवेंचर बेंचने के बहाने व अन्य तरीकों से शेयर मार्केट में हजारों करोड़ के जांलसाजियों कर चुका था। वही हाल अदानी का था जिसने हजारों करोड़ बैंकों से लेकर उनका कर्ज नहीं चुकाया। उन बैंकों के कर्ज की वसूली की अपेक्षा आपने अडानी के भी हजारों करो बैंकों के माफ करवा दिए! और विदेश यात्राओं में भी आपने अपने मित्रों अडानी अंबानी टाटा बिरला के साथ-साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी भारत में उनके व्यवसाय जमाने में जो धन उन्होंने आपके विदेश यात्राओं में हावडी मोदी मैजिक मोदी में खर्च किया था उसकी वसूली के लिए आपने देश में उनके व्यवसाय व अंबानी के लिए देश के उद्योगों को ना केवल नष्ट किया बल्कि उनको मोटा लाभ पहुंचाने 15 करोड़ किसानों को बर्बाद करने के लिए भी आपने कानून तक बनाने से बाज नहीं आ रहे हो।

विदेश यात्राओं में लाखों करोड़ धन की बर्बादी पर हल्ला मचने पर सफाई के नाम पर भी आपने एक तरफ जनता को झाड़ू पकड़ाई। तो दूसरी तरफ सफाई की आड़ में अपने छोटे से छोटे नेता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद और विधायकों सांसदों से लेकर सब की मोटी कमाई करवाने के लिए हजारों करोड़ रुपए के टाटा हिंदूजा महिन्द्रा के हजारों करोड़ के वाहन व अन्य सामग्री खरीद कर मोटे कमीशन से उनकी मोटी कमाई करवाई और अपने पार्टी के लोगों की मोटी कमाई करवाई ताकि हल्ला न हो।

विदेश यात्राओं में आपने जानबूझकर जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपने पांच वार चीन की यात्रा की थी क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन में तो आपकी भारी बदनामी के कारण आप वहां जा नहीं सकते थे उन्होंने आप को प्रतिबंधित किया हुआ था इसलिए आप चीन जा जाकर वहां की कंपनियों उद्योगों व्यवसायियों निवेशकों को पहले गुजरात में बस आते रहे और गुजरात के उद्योग धंधों को हीरे से लेकर कपड़ा रसायन दवा उद्योग पेट्रोलियम इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स आदि अनेकों उद्योगों को चौपट करने के लिए चीनी सस्ते माल चीनी उद्योगों का वहां भरपूर विकास करने के बदले में गुजरात के क्षेत्रीय व्यापारियों उद्योगपतियों को तबाह कर दिया वही हाल अपने देश की सत्ता संभालने के बाद में भी किया और आप चार बार चीन के चक्कर काट कर आए और वहां के उद्योगपतियों कंपनियों मोबाइल उत्पादकों इलेक्ट्रिकल के साथ भारी वाहन भारी मशीनों रसायन दवा आदि के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के उद्योगों को बर्बाद करते हुए और बेरोजगारी बढ़ाते हुए चीन की प्रशंसा आने जाने और जिनपिंग के गले में गर्ल भैया डालते हुए देश को बर्बाद करते रहे जमशेद की बदनामी होने लगी तो आपने देश के ऊपर नोटबंदी लादी ताकि आपके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मित्रों के साथ देसी खास मित्र अंबानी का मोटा फायदा हो उसके पहले आप और आपकी पूरी भैया झुंड पार्टी जो दूरसंचार घोटाले को लेकर हल्ला मचाती थी चिल्लाती चौराहों पर उन सब को आप ने दरकिनार करते हुए अपने मित्र अंबानी को लाइसेंस दे कर देश की दूसरी संचार माध्यमों के साथ बीएसएनल को बर्बाद किया

जब बैंक एक आम आदमी को ऋण देता है। तो अग्रिम हस्तक्षरित चेक लेता है। दी गई ऋण की राशि से कई गुना ज्यादा की संपत्ति पर रहन करता है और उसके बदले में ऋण राशि के भुगतान की ठोस जमानत लेने के साथ-साथ दो अन्य जमानयदरों से भी हस्ताक्षर करवाता है। ऋण राशि समय पर भुगतान अदायगी के संबंध में यदि थोड़ा भी विलंब होता है, तो भी वह ऋण लेने वाले की संपत्ति को कब्जे में ले लेता है साथ ही जमानतदारो की संपत्तियों को भी अपने कब्जे में ले नीलाम कर देता है। तो फिर अदानी कि एक लाख करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ करके उसे और बैंकों से लोन दिलवा कर विदेश यात्राओं में जाकर कभी ऑस्ट्रेलिया में कभी अन्य देशों में उसके लिए अनेकों उन देशों की सरकारों के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में वही हाल अंबानी टाटा बिरला व अन्य पूंजी पतियों के मामले में भी मोदी ने यथार्थ में विदेश यात्राओं में जाकर जो कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते एक तरफ देश का प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बड़े मोटे व्यवसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए जो कि एक प्रधानमंत्री के लिए उसके दायित्व के बाहर का कार्य था। इसके विपरीत न केवल समझौते किए बल्कि बैंकों से ऋण भी दिलवाया जिसमें अदानी की ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदानों का मामला प्रमुखता से समाचार पत्रों में छापा गया वही हाल मुकेश और अनिल अंबानी के मामले में भी मोदी ने किया यहां तक की मोदी ने सारी शर्तों को दरकिनार करते हुए एक फौजी का सबसे पहला लाइसेंस मुकेश अंबानी को दिलवाया और उसके लिए स्वयं टीवी पर आकर विज्ञापन भी किये। जोकि एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के कृत्यों को शोभा नहीं देता था। अपने चुनाव में धन देने वाले मित्रों के लिए उन्होंने सारे नियम कानून त्याग कर सरकारी कंपनियों के साथ-साथ अन्य दूरसंचार कंपनियों को बर्बाद करते हुए इस कृत्य से भी बाज नहीं आए।

विदेश यात्राओं में ज्यादा हल्ला मचा तो उन्होंने लोगों का मुंह बंद करने के लिए सफाई के नाम पर यहां तक की प्रधानमंत्री सचिवालय के अधिकारियों से लेकर देश की ग्राम पंचायतों के सचिवों तक सबको झाड़ू पकड़ा कर सबका ध्यान परिवर्तित करते हुए वहां पर भी अपने पूंजीपति मित्रों टाटा हिंदुजा महिंद्रा से सफाई के नाम नगर निगमों पालिकाओं से लेकर ग्राम पंचायतों तक लगभग एक लाख से ज्यादा मिनी ट्रक खरीदने में मोटा फायदा करवा दिया दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों से लेकर महानगर पालिका नगर निगम को भी वहां बैठे उनके सरपंचों से लेकर सभी पार्षदों निगमों पालिकाओं के अधिकारियों को भी मोटा कमीशन सफाई के नाम पर पेट्रोल डीजल के नाम पर व अन्य सामग्री के नाम पर मोटी कमाई मोटे कमीशन पर करवाई गई ताकि मोदी के खिलाफ किसी भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी की आवाज बुलंद ना हो यह कांड थम भी नहीं पाया था कि अपनी पूंजीपति मित्रों विशेष तौर से मुकेश अंबानी की रिलायंस फ्रेश के साथ टाटा बिरला वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों वॉलमार्ट स्नैपडील अमेजॉन इंडियन टोबैको कंपनी जो ब्रिटिश टोबैको कंपनी की सहायक कंपनी सबड डेढ़ सौ साल से ज्यादा समय से भारत में काम कर रही है अभी भी अंग्रेजों की ही है युनिलीवर अन्य के लिए उनके मोटी लाभ और भारतीय खाद्य वस्तुओं से संबंधित कार्यों के साथ सभी छोटे उद्योगों खत्म करने सभी फुटकर व्यवसायियों हाथ ठेले वालों से लेकर मध्यमवर्गीय उद्योगों को चौपट करने के लिए ताकि नगदी की समस्या के कारण लोग निचले स्तर पर व्यापार ना कर सके और असंगठित क्षेत्र का व्यवसाय पूरा चौपट हो जाए उससे जुड़े लगभग 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो जाए नोटबंदी ला दी गई अवधूत पाखंडी चिल्लाता रहा केवल 50 दिन केवल 50 दिन जबकि नोट की छपाई में भी लगभग 30000 करोड से ज्यादा का जो मुद्रा का कागज होता है उसकी खरीदी भी अंबानी बंधुओं के माध्यम से की गई। और उस नोटबंदी के पाखंड की आड़ में सारे देश के सभी राज्य सरकारों के मंत्रियों अधिकारियों से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों अधिकारियों तक ने भी लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया और सहकारी बैंकों में तो इस घोटाले के जो पुरानी मुद्रा 2 महीने में जमा करनी थी वह छे छे महीने तक मोदी सरकार के और गुजरात के सहकारी बैंकों में जमा होते रहे बड़े स्तर पर मुद्रा परिवर्तन के इस खेल में किसी को कोई घाटा नहीं हुआ पर मरा तो केवल निम्न मध्यमवर्गीय वमध्यमवर्गीय और गरीब आदमी ही। देश में लगभग

40 लाख लघु उद्योग जिसमें करीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यरत है 6 महीने तक नकदी की समस्या से बेरोजगार बैठे रहे नाम दिया गया आतंकवादियों की कमर तोड़ने का पर यथार्थ में कमर तोड़ दी गई 80 करोड़ लोगों की जो दैनिक कमाई करके अपने परिवार चलाते थे। उससे भी इस चांडाल का पेट नहीं भरा तो अपने पूंजीपति मित्रों के लिए अत्यधिक क्लिष्ट जिसे स्वयं भारत सरकार का वित्त मंत्रालय तो दूर बनाने वाले भी जिन्होंने विदेशी पैटर्न से इस जीएसटी के कानून को उठाकर इसीलिए लागू करवाया था ताकि उसके पूंजीपति मित्रों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसकी क्लिष्टता का लाभ उठाकर उसके किंतु परंतु के प्रावधानों में उलझा कर बच निकले और एक मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गीय व्यवसाई लघु उद्योग उत्पादक उस में उलझ जाएं जिनको ये कर संग्रह करने वाले अधिकारी आसानी से कारावास की सजा सुना कर अंदर करवा कर उसका व्यवसाय चौपट कर दें। उसके इस जालसाजी व पाखंड ने देश के लघु उद्योगों को चौपट करने के साथ व्यवसाय उनको खत्म करने में भी अपनी भूमिका अदा की। उससे भी करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए जैसा कि समय माया समाचार पत्र सन 2006 से इस कानून किस बदतमीजी यों का अपने समाचार पत्रों में प्रकाशन करता रहा है क्योंकि 1965 के बाद से इस देश में कोई भी कानून जनता के लिए नहीं बल्कि सारे कानून सभी प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मोटा धन खर्च करके ना केवल देश मगर दुनिया की हर देश में इसी तरह से लात कर वहां के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को देश की जनता को भी छोड़ने मोटी कमाई करने उन देश देश के उन देशों के उद्योग को समाप्त करने के लिए लागू करवाए जाते रहे हैं उसका ही हिस्सा था लादकर बचे कुचे उद्योगों को भी नष्ट कर दिया गया इस प्रकार से सन 2006 से लेकर अभी तक मोदी जनता को केवल दहशत बांटकर देश को और देश की जनता को बर्बाद करता रहा एक तरफ वह दशक बांटकर रूम को झाड़ू नोटबंदी जीएसटी और उसके बाद में और राष्ट्र बंदी के पाखंड में उलझा कर देश की संपत्तियों को जिसमें देश की तेल कंपनियां ओएनजीसी, गैल, भारतीय जीवन बीमा निगम सवा लाख करो रुपए

लेने के बाद में भी उसकी मोटी हिस्सेदारी बाजार में बैचकर पैसा इकट्ठा करना चाहता है। जबकि सरकार ने पीयरलेस कंपनी को अधिग्रहित करके माय व्यवसाय और राष्ट्रीय कृत कर दिया था सरकार ने उस पर लगाया क्या जो यह अपने बाप की जागीर समझ कर उसको बैचने की तैयारी में है। जो राक्षस मोदी, अपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए जमाने को सूचना का अधिकार का पाठ पढ़ाकर जानकारी मांगने के लिए बोलता कहत था। वह यह नहीं बताता कि रिजर्व बैंक से किस्तों किस्तों में उसने लगभग 41लाख करोड रुपए जो खाली किए वह कहां गए उसका हिसाब क्या है दूसरी तरफ जो पेट्रोल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटकर 30 $25 पर आ जाने के बावजूद भी भारत में तेल की कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा होने के उपरांत वह है हजारों का ऊपर प्रति दिन की कमाई जो पेट्रोल से हो रही है वह कहां जा रही है उसका भी कोई हिसाब नहीं विदेशी बैंकों से जिसमें विशेष तो उसे विश्व बैंक एशियन विकास बैंक व अन्य संस्थाओं से लाखों-करोड़ों पर का जोड़ लिया वह कहां गया?

456 रेलवे स्टेशन बेंचे, रेलवे की जमीनों को नीलाम किया जा रहा है, 151 ट्रेनों को, निजी क्षेत्र में देकर मोटी वसूली की जा रही है सामने से बोली छोटी लगती है पर पीछे सैकड़ों करोड़ का कारोबार एक गुजराती धूर्त तेली जिसकी रग रग में व्यवसाय बसा हुआ है, हवाई अड्डे किराए पर उठाए उसका धन कहां गया। भारत संचार निगम लिमिटेड को 4उ का लाइसेंस सालों बाद दिया गया उसके पहले अपने बाप मुकेश अंबानी को 4जी का लाइसेंस देकर पूरे देश में उसकी 30 करोड़ से अधिक सिम बिकवा दी। कोयला खदाने, मायका आयरन, तांबे आदि की खजाने की मूवी बाले बाले अपने मित्रों को लुटा दी गई। जिसके कानों कान किसी की खबर नहीं 40000 किलोमीटर सड़कें भी अपने मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से ब्यूटी में देकर मोटी कमाई करवाई जा रही है वही हाल विद्युत जिसमें परमाणु ऊर्जा का अहम रोल है देश की परमाणु भट्टी यों के लिए देश के थोरियम का उपयोग नहीं किया जाता उसके लिए यूरेनियम की खरीदी बाले बाले हजारों करोड़ में विदेशी संस्थाओं से करी जाती है यह बातें हैं जो सामने ही नहीं आई है। वर्तमान में चल रहे कोरोना के पाखंड की आड़ में सच तो यह है जिसे 22 मार्च को मैंने अपने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से लोगों को यह स्पष्ट कर दिया था कि सारी कहानी पूरे बाजार को चौपट कर के जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 06 में स्पष्ट व्याख्या थी की कानूनी जड़ों में उलझा कर सारी मंडियां सारे बाजार सारे फुटकर व्यवसाय को समाप्त करके केवल बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट अमेजॉन के साथ यूनीलीवर, आईटीसी जो कि ब्रिटिश टोबेको कंपनी की डेढ़ सौ साल पुरानी भारत में प्रतिनिधि कंपनी भारत में अंग्रेजो के द्वारा बनाई व भारतीय कर्मचारियों से चलवाई जा रही है।

भारत में अंबानी की जिओ मार्ट रिलायंस रिटेल के साथ टाटा बिरला वाह अदानी जोकि साइलो के अपने गोडाउन में किसानों के सारे माल को इस महामारी की आड़ में देवास की ही मंडी को बंद करवा कर जहां मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की कीमत 1925 रुपए निर्धारित की थी को को मंडी बंद करवा कर 1617 100 अट्ठारह सौ में हजारों टन गेहूं खरीद कर अपने साइलो के गोडाउन में भर लिया जबकि यह कहानी देवास के नहीं पूरे देश के अनेकों केंद्रों पर हुई और जो मोदी अभी अध्यादेश लेकर आया है इस पाखंड की आड़ में उनका उद्देश्य किसानों की जमीनों पर कब्जे करने से लेकर जहां पर वह है अपनी ठेका खेती जिसमें खेतों को पट्टे पर, किराए पर लेकर खेतों के मालिकों को उन्हीं के खेतों पर नौकर बनाकर उन्हें दैनिक वेतन की सरकारी मजदूरी से भी कम मजदूरी देकर अपने बीच अपनी खास वाह यांत्रिक खेती से पूरी फसलों पर कब्जा करने का षड्यंत्र है यह पट्टे और किराए का भी कर्नाटक है कि 1 साल 2 साल चलेगा। 3-4 साल में उस खेत के मालिकों को षड्यंत्र और कानूनों में फंसाकर खेतों को ही हजम कर

लिया जाएगा। छोटे खाद्य वस्तुओं से संबंधित उद्योग, दाल उद्योग चावल कुटाई, पालिश, सफाई, शक्कर तेल आदि के सभी उद्योगों पर इन चांडाल बहुराष्ट्रीय और देसी कंपनियों की जो निगाहें लगी हुई है उनका उद्देश्य पूरे कृषि व्यवसाय पर कब्जा करना ही है ताकि उसको अपने गोदामों में भरकर अपनी मनमानी कीमतों पर लूट सके जैसे चांद आलू की फौज देसी विदेशी सब अमर फल खा कर आई है और सारा व्यवसाय देश की बैंक के तेल बीमा रेलवे खाद्य उद्योग परिवहन शिक्षा को अपने सीने पर रखकर बस छोटे से पाखंड में कि यह मेरा है बर्बाद करने पर तुले हुए हैं जिसमें चांडाल मोदी आंख मीच कर ये भुखेरा भेड़िया सब सपने पर तुला है यथार्थ में जितने लोग संक्रमित होना और मृत्यु होना दिखाए जा रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा लोग पिछले 15,-20 सालों से मरते रहे हैं 8000 लोग प्रतिदिन सर्दी खांसी जुकाम बुखार जन्य बीमारियों यथा फ्लू वायरल स्वाइन फ्लू टेमीफ्लू माता इनफ्लुएंजा निमोनिया सांस अस्थमा टीवी आदि से मरने का औसत रहा है। यदि हम 6 महीने का औसत लगा कर देखें तो 180 दिन में 14,40 हजार लोग मरने थे। वही हाल 25 दिन 8000 लोग कैंसर से मरने का 9000 लोग हृदय आघात से मरने का 7 से 8000 लोग प्रतिदिन सड़कों पर दुर्घटनाओं में मरने का औसत पूर्व से रहा है इसके विपरीत हम अगर ग्राहक आंकड़ों पर देखें तो 140 करोड़ की आबादी में जहां रोज डेढ़ लाख बच्चे पैदा होते हैं वहां 50000 व्यक्तियों की पूरे देश में मृत्यु होना स्वभाविक सी प्रक्रिया है कितने मर गए फिर यह प्रकृति जन्म सत्य है कि हर बदलते मौसम में ना केवल मनुष्यों को बल्कि अन्य सभी प्राणी भी मौसम के वाह तापमान के उच्चावचन से न केवल सर्दी खांसी से वरुण अन्य बीमारियों से और कमजोर दिल के और बूढ़े लोग सबसे ज्यादा हृदयाघात से मरते हैं तो फिर नया क्या हो गया 140 करोड़ की आबादी में यदि 7000000 लोग भी संक्रमित हुए तो कुल आबादी के मात्र 0.00 0 5इ ही होते हैं तो नया क्या हो गया फिर भी उस पाखंड की आड़ में मूल उद्देश्य ही था कि सारे बाजारों को मंडियों को उद्योगों को बंद कर आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाए ताकि सब का सब बंद हो जाए और भाई साहब बंद होकर पूंजीपतियों के शॉपिंग मॉल की तरफ उनकी मनमानी कीमतों को देकर आम जन जीवन यापन करें उसी के लिए खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया गया जहां पर एक रुपए किलो गेहूं और रु. 2 किलो का चावल देकर पेट की भूख को मुंह में मुफ्त की रोटी फंसा कर करूं बेरोजगार मजदूरों को चुप रखा जा सके। अर्थात मोदी ने पूंजी पतियों की रखैल बन कर सारी विदेश यात्राएं सफाई कार्यक्रम नोटबंदी जीएसटी और यह महामारी का पाखंड उनके लिए उनके इशारे पर ही किया।

इंटरनेट होता जा रहा घातक, कदम- २
आनलाइन ठगोरों का जाल

आपकी एटीएम का क्लोन तैयार करना घंटों की बात नहीं मिनटों की बात हो चुकी है। आप किसी भी दुकान में जाकर जब एटीएम से पेमेंट करते हैं तो सामने वाला अपनी मुट्ठी में बंद एटीएम क्लोन मशीन से आपके एटीएम का जानकारी लेकर उसे कुछ मिनटों में ही दूसरा एटीएम क्लोन तैयार कर लेता है। और आपके पैसे साफ कर देता है।

कितना घातक है? रोज ही लाखों लोगों के अकाउंट से इन्हीं ऑनलाइन सेवाओं में इंटरनेट एटीएम पेटीएम के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हो रही है। पर आप हैं कि अपने आधुनिकता के अंदाज में अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं अभी भी वक्त है। कि आप नगद रोकड़े का लेन देन और बैंकों में भी बिना कार्ड के चेक से डायरेक्ट पेमेंट विड्रॉल और जमा करने का पुराना कार्य पर लौट आए। वैसे तो यूरोप में सारे ऑनलाइन और स्केच करने वाले पेमेंट अधिकतर जगह पर इन्हीं जालसाजी के चलते बंद किए जाने लगे हैं। अकेले भारत में हर मिनट में लगभग 40 लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। जिसमें से 35 लोग अंजान बने रहते हैं।

5 लोग जानकर तत्काल बैंकों को और सरकार की पुलिस को

सूचित करते हैं। पिछले साल लगभग 70 लाख से ज्यादा लोगों के साथ इन्हीं ऑनलाइन स्केच एटीएम पेटीएम से कैसे ठगी की गई है। यह सरकारी आंकड़े हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई और जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई उनमें करोड़ों को मालूम ही नहीं होगा कि वह ठगे जा चुके हैं। हर जगह अपने नंबर मोबाइल नंबर बांटना। यूट्यूब गूगल आदि से अपने मोबाइल पर सर्च करना उल्टे सीधे मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना गेम खेलने के चक्कर में आपकी सारी मोबाइल की जानकारियां संबंधित ऐप के साथ-साथ गूगल यूट्यूब आदि पर जाती रहती है जिसमें आपकी धन संबंधी भुगतान प्राप्ति बैंक अकाउंट आदि की जानकारियां भी आसानी से ठगी का शिकार बनाने वालों के हाथ में पहुंचती रहती हैं। समझें और ठगी से बचें अन्यथा कब कंगाल होकर सड़क पर कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं। पिछले 15 सालों से भारत सरकार की अपने समाचार पत्र के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से लगातार लिखा जा रहा है कि भारत का सारा डाटा ई-मेल से जीमेल से आधार कार्ड से सारी जानकारियां विदेशों में माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल व अन्य हजारों साफ्टवेयर कंपनियों के पास एकत्रित हो विश का भारी दुरुपयोग विश्लेषण अपने व्यवसायिक उद्देश्य से लाभ कमाने के लिए कर रही है। सरकार को चाहिए कि वह सब बैंकों का बीमा कंपनियों व सभी मंत्रालयों दूरसंचार से लेकर रक्षा शिक्षा स्वास्थ्य आदि का प्रबंधन स्वयं भारत सरकार को अपने देश में हीं करना चाहिए।

इसके विपरीत सरकार उल्टे ही जो शासकीय स्तर के केंद्र राज्य बैंकों बीमा कंपनियों नगर निगम पालिका से लेकर सभी विभागों के अपने अपने मोबाइल एप भुगतान एप जिसमें भीम यूपीआई पेटीएम आदि सैकड़ों प्रकार के ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल के माध्यम से करने के लिए बोल कह व करवा रही है। जिसके माध्यम से करोड़ों लोग प्रतिदिन अनेकों प्रकार की ठगी जिसमें बैंकों से पेटीएम पेटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड 27 से निकालने के साथ-साथ लोगों के सारे डाटा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहुंचकर देश की जनता शासकीय विभागों से लेकर वित्तीय रक्षा स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लाखों संस्थानों की भी गोपी का भंग होने के साथ-साथ उनकी डेट आज का भी भारी व्यवसायिक उद्देश पूरी दुनिया में किया जा रहा है और सरकार केतने और जागने को तैयार ही नहीं है। उसके राज्यों की पुलिस स्वयं डकैती में अनेकों स्थानों पर हिस्सेदारी कर ऐसे हैकरों और डकैतों को पालती है। अधिकांश सरकारी और निजी बैंकों का जिसमें स्टेट बैंक उसके कर्मचारी और अधिकारी जो स्वयं भ्रष्ट जालसाज और घोर बदतमीज भी होते ही है जानबूझकर 99.9 प्रतिशत शिकायतों को लेने से ही मना कर देते हैं स्वयं बहुत सारी जालसाजी दोनों साथ मिलकर उन्हें बैंकों की आंतरिक को बाहरी जानकारी उपलब्ध करवाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इसलिए ऐसी 99.9इ चोरी डकैतीया खातों से पैसे गायब होना देवी के गीत पेटीएम एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाना यहां हर पल 24 घंटे चलता रहता है ना ही बैंक और ना ही पुलिस आमजन की कोई मदद कर पाती है लुट जाने के बाद ग्राहक पुलिस बैंक के बीच में फुटबॉल बना घूमता रह कर अपनी जिंदगी तबाह करता रहता है तन मन धन से।

दूसरी तरफ यह सरकार यह सब जानकर भी कि हर मिनट में 30 से 40 लोग इन ठगों का शिकार बन रहे हैं ना तो अपनी कार्यप्रणाली को संचार साधनों बैंकों बीमा कंपनियों आदि आदि से अपनी जानकारियों को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा पा रही है ना ही जनहित ओं का सरंक्षण कर पा रही है इसके विपरीत वह अधिकतम लेनदेन को ऑनलाइन करना चाहती है अर्थात यह सिद्ध करता है कि सरकार में बैठे हुए अधिकांश अधिकारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच कर उनका डाटा एकत्रित करवाने भविष्य में उनके मोटे लाभ के लिए जालसाजीपुर्ण प्रबंधन कर रही है।

शासन की योजनाओं में पलीता दिखाने अनुदान को हड़पने
कृषि विभाग में मचा हुआ है लूट का तांडव
कर्मचारी अपने ही विभाग के लोगों को नहीं छोड़ते तो किसानों को कैसे छोड़ेंगे

भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से ही यथार्थ ने वर्तमान में भी पूरा देश चल रहा है। यह स्पष्ट है इसके विपरीत वर्तमान की भूखे भेड़ियों झुंड पार्टी के गुजराती मोदी जिसका प्रधानमंत्री क्या बना पूंजी पतियों के रखैल भूखे राक्षस को पूरे देश को बर्बाद करने का मौका मिल गया।

पिछले 6 सालों में देश को बर्बादी देने की अतिरिक्त यह हरामखोर कुछ नहीं कर सका जो उसके सामने आता है राक्षस देश की 140 करोड जनता को निचोड़ कर बर्बाद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है इसी श्रंखला में सबसे महत्वपूर्ण देश का आर्थिक घटक कृषि और उसके उपजें खाद्यान्न दलहन तिलहन मसाले फल फूल और देश की काली मिट्टी की कृषि भूमि पर दुनिया के कृषि विभाग को केंद्र शासन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दूसरी राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन तीसरा राष्ट्रीय तिलहन बीज चौथी राष्ट्रीय कृषि विकास एवं तकनीकी मिशन पांचवा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना छठवां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सातवा परंपरागत कृषि विकास योजना आठवां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 9वी कृषि भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना दसवीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और 11वीं कृषि वानिकी विकास योजना राज्य पोषित योजनाओं में अन्नपूर्णा योजना एवं सूरज धारा योजना दूसरा राष्ट्रीय जैविक वायु योजना तीसरा नलकूप खनन योजना चौथा मध्य प्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी मावा योजना को सरकार ने 25 सितंबर 2020 को खत्म कर दिया है पांचवा आत्मा योजना छठवां मृदा परीक्षण व मृदा स्वास्थ्य पत्रक सातवास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि विस्तार आठवां मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना इसे भी सरकार ने 25 सितंबर 2020 को खत्म कर दिया है नवा प्रदेश में गुण नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला में इन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अकेले सूरज धारा योजना के अंतर्गत बीज लाभ अदला-बदली में पंद्रह रु.100 की भी 1526 प्रमाणित बीज का है।

इस प्रकार से इन सारी योजनाओं में पूरे मध्यप्रदेश में हर उपसंचालक जिला में बैठे हुए बिजी 25 25 साल से बैठे हुए वहां के बाबू और कर्मचारी के साथ में 15 10 15 20 वालों से बैठे हुए वहां के सहायक संचालक और उपसंचालक मिलकर किसानों के साथ छल कपट करते हुए करोड़ों रुपए का अनुदान उनके खातों में पहुंचाने की अपेक्षा भिंड अपने ही विभाग के कर्मचारियों के खातों में अंतरित करवा कर हजम कर जाते हैं यही कारण है कि इंदौर के में बैठे रामेश्वर पटेल उप संचालक कृषि मैं बैठा हुआ मोटी कमाई करने के लिए ही यहां पर आया है और वहां बैठा बाबू कना आज रात में इन सारे दो नंबरों को काम करने के लिए 12:00 से 1:00 1:30 बजे रात तक ऑफिस में बैठकर यह सारे छल पूर्ण कार्यों को अंजाम देता है फिर इंदौर में सारे प्रदेश के उपसंचालक क्यों स्थानांतरण पाने की कोशिश करते हैं मात्र यहां पर मोटी कमाई का साधन ना केवल यह अनुदान बल्कि जितने भी देश भर की कंपनियां जो बीज उत्पादन खाद उत्पादन कीटनाशक उत्पादन करने वाली हैं उनके सबके कार्यालय भी इंदौर में ही हैं जैविक खाद के नाम पर तो आप देख ही रहे हैं कैसी लूटपाट चालकर मची हुई है उनके नमूने लेने पास करने फेल करने की मैं भी मोटा खेल बसूली का होता है और यह पिछले 25 साल से यहां लगातार चल रहा है क्योंकि अगर यहां किसी खाद बीज और कीटनाशक उत्पादन विक्रेता कंपनियों के नमूने फाइल कर दी जाते हैं तो वह पूरे मध्यप्रदेश को अवसर करते हैं।

इसलिए यहां मोटी कमाई उपसंचालक की होती है और वहां बैठने के लिए लालायित रहता है बेशक जो है धन देने के लिए होता है और उनके यहां बैठ पाता है यही हाल वैसे तो प्रदेश के हर जिले में है और वहां मोटी कमाई इन अनुदान योजनाओं में बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं में की जाती है देवास में भी जो अभी उपसंचालक चौहान बैठी हुई है वही है और जानकारी देने के नाम पर बार-बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को बहुत ईमानदार बनती हैं जबकि सूत्रों के अनुसार वह मूल रूप से मोटी कमाई करके मॉडर्न पहुंचा कर ही वहां बैठी हुई है

साप्ताहिक समय माया

लोक निर्माण विभाग के अधिकांश पद प्रभारियों के हवाले

प्रभारियों से मोटी वसूली के बाद पद और फिर महीना भी

माइ के लाल कंस मामू अपनी लूट के लिए न्यायालय के आदेशों के बाद भी मोटी वसूली के लिए नहीं कर रहा सभी विभागों में पदोन्नतियां

प्रदेश भर में सत्ता को हटाने के बाद पिछले 6 महीने में लूटमार भ्रष्टाचार महामारी के पाखंड की आड़ में बहुत खुलकर किया गया बेशक सामने से सब कुछ बंद था पर मंत्रालय और मंत्रिमंडल की मीटिंग में सब कुछ खुल कर चलता रहा वैसे भी पूर्व में 13 साल शिवराज ने लगातार सत्ता संभाल कर चारों तरफ हर विभाग में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर लाखों-करोड़ों इकट्ठे किए जिसमें आपने देखा बड़ी आसानी से मार्च के महीने में हजारों करोड़ खर्च कर विधायक खरीदे गए और केंद्र के ना चाहने पर भी हजारों करोड़ का मोटा धन खर्च कर मध्यप्रदेश में शिवराज ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। आखिर क्यों?

मात्र भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार के लिए, लोकतंत्र की हत्या की गई। स्वाभाविक था की आते ही हर विभाग में उस खर्च की गई धन की वसूली के लिए चुन-चुन के घोर भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्रालय देकर चुन-चुन के घोर भ्रष्ट अधिकारियों को प्रभार में बैठाया गया हर संभाग में हर मंडल कार्यालय में हर आंचलिक से लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तक ताकि जितने भी महीने सरकार चले लूटपाट कर वसूली की जाए जैसा कि भेड़िया ढूंढ पार्टी का प्रादुर्भाव से लेकर आज तक कार्यक्रम रहा है। इसी का परिणाम था थोड़ी तेज बारिश होने में पुल बह गए सड़कें बह गई। परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा निर्माण किये भवनों में पानी टपकता रहा। सभी सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों अधिकारियों के निवास भवनों मैं रखरखाव लिपाई पुताई का वार्षिक रखरखाव का सारा पैसा उपयंत्री सहायक व कार्यपालन यंत्री तक सभी संभागों में हजम करते रहे।

वही हाल सड़कों व पुलों को सुधार के नाम पर भी पैसा हजम किया जाता रहा जिनकी निविदाएं प्रकाशित की गई करोड़ों के कार्यों के निविदाओं को टुकड़े-टुकड़े कर 20लाख रुपए से नीचे के लगाए गए और वह सारा पैसा भी हर संभाग में कागजों पर ही हजम किया जाता रहा। क्योंकि आखिर उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों को भी उच्च पद पर बैठने के लिए एकमुश्त पहले ठेके की राशि का भुगतान करने के साथ मासिक व स्थानांतरण, पदस्थी और स्थाई रहने के नाम पर ना केवल अपने प्रमुख अभियंता सचिव प्रधान सचिव और मंत्रियों को भी मोटे धन का भुगतान करने के साथ ही अपने संभाग के प्रभारी मंत्री वहां के निवासरत विधायक और मंत्री के आने-जाने खाने-पीने ठहरने रहने विश्राम गृह में स्वयं के रहने के साथ अपने चलो और पशुओं को रखने खिलाने पिलाने का खर्च भी इन्हीं बेचारे उपयंत्रियों, सहायक व कार्यपालन यंत्री यों को अपनी जेब से करना पड़ता है आखिर लाखों रुपए के इस भ्रष्टाचार को जो इन घोर फर्स्ट नंगे भूखे विधायकों, मंत्रियों प्रभारी मंत्री आदि को करना पड़ता है तो आखिर लाएंगे कहां से स्वाभाविक सी बात है यह शिष्टाचार पूरा करने के लिए कहीं से तो वह कर्मचारी और अधिकारी धन निकालकर बांटेगा और खर्च करेगा ही। अन्यथा यह आपराधिक मानसिकता के गुंडे बदमाश नेताओं द्वारा जो किस्मत का छींका टूटते ही चुने जाने और मंत्री बन जाने पर उसका सार्वजनिक रूप से अपमान करने डांटने फटकिरने के साथ-साथ वर्षों से एक ही जगह सड़ाये जा रहे कर्मचारियों, अधिकारियों यंत्रियों को आर्थिक व सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है इससे बचने वह मजबूरी बस भ्रष्टाचार करने के लिए बाध्य होते हैं। फिर मुख्यमंत्री शिवराज का तो ब्रह्म वाक्य हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमार के दम पर ही तो तेरा साल शासन किया था। उसको पूरा करते हुए 6 महीने में सत्ता संभालने के बाद ही उन्होंने चुन चुन कर जो सहायक मानचित्र कार्ड थे उनको उपयंत्री का उपयंत्री यों को सहायक यंत्री का सहायक यंत्री यों को कार्यपालन यंत्री का कार्यपालन यंत्री यों को अधीक्षण यंत्री का और अधीक्षण यंत्री को मुख्य अभियंता का चंद्रप्रकाश अग्रवाल मुख्य अभियंता को प्रमुख अभियंता पद का प्रभार सौंप कर मोटी वसूली की व्यवस्था ही तो की है। अब अगर पुल, सड़कें बह रहे हो तो बह जाएं। जनता परेशान हो रही हो वाहनों के टायर फट रहे हो वाहन में टूट-फूट हो रही हो दुर्घटनाओं में लोग मर रहे हो तो यह भेडियो के झुंड पार्टी को इससे क्या फर्क पड़ता है जनता मरने के लिए ही पैदा हुई है क्योंकि वोट जनता ने ही नहीं इन विधायकों को दिया था।

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई में पूर्व का सेवा निर्वत घोर भ्रष्ट पूर्व का प्रमुख अभीयंता अखिलेश अग्रवाल वर्तमान में परियोजना संचालक बनकर बैठा हुआ है स्वभाविक सी बात है जब मोटा पैसा देकर सेवानिवृत्ति के बाद पुनः विभाग में परियोजना संचालक बनकर बैठा है। तो पावन उद्देश्य वसूली का ही है। इसलिए प्रदेश भर में बन रहे सभी विभागों इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, न्यायिक विभाग, पशु चिकित्सालय, कृषि, उद्यानिकी, परिवहन आदि अनेक विभागों के जो भवन निर्माण का सारा कार्य जो यह क्रियान्वयन इकाई करती आ रही है। भवन निर्माण में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के भवनों के संबंध में पहले भी पूर्व में शिकायतें आ चुकी हैं, और कईयों में लोकायुक्त कार्रवाई भी हो चुकी है। एक ही लोक निर्माण विभाग के योग और भ्रष्ट इंजीनियर विभाग में काम नहीं करते थे। उनको इस विभाग में अंतरित कर दिया गया है और कुछ विभाग की बेरुखी से इस विभाग में स्थानांतरण लेकर आ कर बैठ गये हैं। इस वि?भाग में हर स्तर पर आधा खेल नक्शा बदलने नक्शों को ठेकों में बनवाने मैं जानबूझकर निजी कंपनियां मोटे बजट के भारी-भरकम बजट बना कर देती है क्योंकि उसमें जो निश्चित कमीशन नक्शा बनाने का मिलता है। वह उतना ही भारी हो जाता है।

लोक निर्माण विभाग की इस इकाई में सारा काम ठेको पर होता है यहां तक की सारे भवनों के निर्माण में सारी एमबी आ भी ठेके के कर्मचारी जो ठेके पर आते हैं वार्ड नए लड़के जिन्होंने हाल ही में इंजीनियरिंग पास किया होता है भर्ती किए जाते हैं। वही सारी मां पुस्तिकाओं में सारे भवनों के प्रति जिनकी किए हुए ठेकेदारों के कार्यों को नाप लेकर भरते हैं और उसी के आधार पर सारे बिलों की स्वीकृति वहां का उपयंत्री जांच कर सहायक यंत्री को देकर इन बिलों को पास करवाता है स्वभाविक सी बात है कि विभाग का यथार्थ में कोई भी नियमित कर्मचारी अधिकारी उन भवनों की सीधी देखरेख में नहीं होता और इसलिए ठेकेदार इसका भरपूर फायदा उठाकर भवनों को यथा योग्य तरीके से मोटी कमाई करते हुए और बांटते हुए निर्माण करता है क्योंकि पूर्व में अधिकांश भवनों के निर्माण में लोड फैक्टर में काफी रकम अजान की गई जिस तरीके से भवनों के बड़े लंबे चौड़े डीपीआरओ डिजाइन नक्शे तैयार किए जाते हैं वह नक्शे प्रायोगिक तौर पर जब भवनों का निर्माण होता है तो उनमें काफी हेरफेर और उनके अनुसार उस तरीके से काम नहीं किया जाता जब की राशि उसी के हिसाब से स्वीकृत की जाती है और इस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है यह कहानी पिछले 10 साल से प्रदेश के सभी परियोजना किरण इकाइयों में चल रही है और यही कारण है की प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल सेवानिवृत्त होने के बाद में भी मोटा धन खर्च कर यहां पर परियोजना संचालक के रूप में मोटी कमाई के लिए ही आकर कुंडली मारकर बैठा है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सभी आयातित इंजीनियर भ्रष्टाचार करो और चलो

ठेकेदारों के साथ मिलकर गुणवत्ता का कारण ही वसूली की व्यवस्था

मध्य प्रदेश ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण में उसके प्रारंभ से लेकर अभी तक यहां पर सभी इंजीनियर ग्रामीण यांत्रिकी से लेकर लोक निर्माण विभाग जल संसाधन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी गृह निर्माण औद्योगिक केंद्र विकास निगम, से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कंपनियों के इंजीनियरों तकिया पदस्थ की जाती है जिनका दूर-दूर तक सड़क से कोई वास्ता नहीं होता बैठा दिए जाते हैं।

स्वाभाविक है कि उन्हें सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा के समय का ही जो ज्ञान होता है उसी के दम पर वे एस ग्राम सड़क परियोजना कार्य में कार्य करने के लिए आ जाते हैं स्वाभाविक है उनके लिए सड़कों का स्तर कार्य की पद्धति कार्य की गुणवत्ता से कहीं ज्यादा क्योंकि वह धन खर्च करके ही इस विभाग में आते हैं स्वाभाविक सी बात है कार्य गुणवत्ता की अपेक्षा मोटी कमाई का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण में सारी भूमि ग्रामीणों से पंचायतों की सरकारी चरनोई की नजूल की मुफ्त की भूमि का ही सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। निसंदेह गांव की सड़कों से जोड़ने पर ग्रामीणों को खुशी तो होती है पर यह खुशी तब दुख में बदल जाती है जब किसान का सड़कों के निर्माण के कारण बरसात के दिनों में सड़क के गलत तरीके से और पानी की पर्याप्त निकासी ना होने के कारण सड़कों के बन जाने के कारण उनके खेतों में भर जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है स्वाभाविक सी बात है जिन इंजीनियरों को इस बात का एहसास ही नहीं होता क्योंकि सड़क निर्माण के बाद पानी की पर्याप्त निकासी ना देने के कारण जिन किसानों ने अपनी भूमि सड़क निर्माण के लिए दान में दी थी वह उनकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। जिसके पीछे यही आयातित इंजीनियरों का अधूरा और उथला ज्ञान ही जिम्मेदार होता है और हर जिले में बनी हुई परियोजना क्रियान्वयन ईकाई द्वारा बनाई हुई सड़कों में हर सड़क से जुड़ा हुआ ऐसा खेत जिसमें निर्माण के समय पानी की सड़क की ऊंचाई बढ़ जाने के कारण पर्याप्त निकासी ना होने से दस बीस परसेंट सड़क किनारे के गांवों को यह नुकसान लगातार झेलना पड़ रहा है जिसके लिए यहां के डीपीआर बनाने वाले उपयंत्री सहायक यंत्री महाप्रबंधक से लेकर मुख्य महाप्रबंधक तक सब जिम्मेदार होते हैं परंतु भ्रष्टाचार के

चलते किसानों की ऐसी आवाज को कोई नहीं सुनता जबकि होना यह चाहिए की पहली ही बरसात में सड़क बन जाने के बाद ऐसे जितने भी किसान इस संकट के शिकार हुए हैं उन्हें अगली बरसात आने से पहले उनके खेतों में पर्याप्त जल निकासी के लिए छोटी पुलिया की व्यवस्था की जानी चाहिए दूसरी तरफ सच यह भी है की सड़क निर्माण के बाद दोनों तरफ खुदी जाने वाली नालियों का निर्माण ही ढंग से नहीं होता जबकि हर सड़क निर्माण के प्रक्रम में नालियों के निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था का व्यवहारिक प्रावधान किया जाता है परंतु भ्रष्टाचार के साथ चलते और आयातित इंजीनियरों की वसूली की मानसिकता के चलते दोनों तरफ पर्याप्त नालियों की खुदाई नहीं होती है साथ ही साडे 6 मीटर की सड़क में दोनों तरफ डेढ़ लीटर की पट्टियां भरने में भी जो कच्ची मोरम से सड़क तक समतल पट्टियां भरी जानी चाहिए उनमें भी ढंग से भराई नहीं की जाती। और पैसा हजम कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हर छोटे से छोटे गांवों में वाहनों की संख्या में न केवल मोटरसाइकिल बल्कि चार पहिया वाहनों, ट्रैक्टरों ,कारों, मिनी ट्रकों की भी पिछले 10 सालों में काफी वृद्धि हो चुकी है स्वभाविक है की सड़कों पर यातायात का भार बढ़ने से यह सड़कें कम से कम 9 मीटर होनी चाहिए जिसमें 6 मीटर डामरी कृत वाहन चलने योग्य सड़क व डेढ़ मीटर की दोनों तरफ सोल्डर पटिया होनी चाहिए। क्योंकि वाहनों के बढ़ने से गांव के युवा बच्चे सड़कों की चौड़ाई कम होने से सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त इन्हीं सड़कों पर सामने से आने वाले वाहन के कारण हो रहे हैं। जो कुल 9 मीटर की चौड़ाई भविष्य के लिए आवश्यक है। परंतु वर्तमान में 3.75 मीटर की सड़क और 1.125 मीटर की दोनों तरफ की सोल्डर पट्टियों का निर्माण किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ आप इस चित्र में देख रहे हैं मिट्टी कार्य को भी पानी डालकर रोलर कैसे दबाया बनाया जाना चाहिए दानेदार उप आधार को भी पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ मोरम होना चाहिए जो की गिट्टी या नदी की रेत से पत्थर का चूरा भरा जाना चाहिए वह सब कुछ नहीं होता वहीं की काली मिट्टी को पलटा कर उसमें ही पत्थरो व गिट्टी की भराई करके कार्य संपन्न करके मोटा पैसा हजम कर लिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है इस मोटी कमाई का हिस्सा उपयंत्री सहायक यंत्री के साथ महाप्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक प्रमुख अभियंता सीईओ सड़क विकास प्राधिकरण मंत्री ग्रामीण विकास प्रधान सचिव ग्रामीण विकास मैं बढ़ने के साथ-साथ गांव के सरपंच वहां के विधायक और सांसद को भी हिस्सा बांटना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है पैसा भले ही केंद्र सरकार दे बेशक केंद्र सरकार के मापदंड बहुत ठोस और स्तरीय होते हैं पर कार्य करवाने वाले घोर भ्रष्ट होते हैं इसलिए यह कार्यक्षमता गारंटी की सड़कें दी समय पूर्व खराब हो जाती हैं।

यही कारण है कि सूचना के अधिकार में जानकारी ना देने के लिए कम से कम इंदौर संभाग की 10 से ज्यादा इकाइयों में घोर भ्रष्ट इंजीनियर होने के कारण वह बहाने ज्यादा बनाते हैं और उनके संरक्षक मुख्य महाप्रबंधक विजय श्रीवास्तव पहले तो अकेले ही पी जाते हैं पर ज्यादा दबाव डालने पर सारी सुनवाई करने के बाद मैं भी अपने महीना बांटने वाले महा प्रबंधकों को बचाने के लिए उल्टे सीधे आदेश देकर जानकारी देने से आवेदकों को वंचित करने का प्रयास करते हैं। वैसे इसके पूर्व में भी बिलों की वसूली में कई इंजीनियर प्रदेश भर में और लोकायुक्त के लपेटे में आ चुके हैं।

भाजपा कब संशोधन करेगी संविधान के अनुच्छेद 30A का

प्रतिबंधित है पौराणिक ज्ञान एवं हिंदू शास्त्रों की शिक्षा का पठन पाठन

वर्तमान में इंटरनेट और कंप्यूटरीकृत युग है। जहां उनके सॉफ्टवेयर या अन्य सेवा के उपयोग से पहले आपको वसूली के माध्यम के लिए आपसे आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड की भुगतान के तरीकों की जानकारी मांगी जाती है। जो सेवाएं कंपनियां आपको इंटरनेट पर मुफ्त सॉफ्टवेयर की व्यवस्थाएं देती है। या सोशल साइट्स की व्यवस्थाएं देती हैं। वह पहले आपसे आपकी कंप्यूटर, मोबाइल आदि में आपकी बातचीत को सुनने से लेकर, आपके मोबाइल की संपर्कों की सूची, उस में पड़े हुए चित्र, चलचित्र, दस्तावेजों, व अन्य सभी सामग्री को देखने, उसमे ताकने, झांकने, उपयोग करने की चेतावनी दे देती हैं। उसकी आप को बिना सूचित किए स्वतंत्रता मांगती है।

यदि आप उसको न करते हो। तो वे आपको उसको उपयोग करने नहीं देती हैं। और वह सभी इंटरनेट की गूगल जैसी आभासी कंपनियां जो आपको सोशल साइट्स ईमेल या अन्य सेवाएं निशुल्क दे रही हैं। सच तो यह है, कि?

आपके मर्जी और बिना बताए ही आपके सारी जानकारियां आपकी. आपके परिवार, मित्रों, शत्रुओं की सोच बातचीत चित्र चलचित्र पत्राचार से लेकर आदतों, खाने पीने आने जाने, बीमारी, दवा, सांस लेने आदि तक हर डाटा का खुलकर भरपूर विश्लेषण, व्यावसायिक सदुपयोग करती हैं यदि आप उन्हें उपयोग करने की चेतावनी पर मना करते हैं तो वे आपको उन सेवाओं को प्रयोग नहीं करने देती हैं यह कार्य पिछले 15 सालों से बखूबी पूरी दुनिया में खूब फल फूल रहा है।

वर्तमान हालत यह है कि अब उपयोगकर्ता की सांसों की गिनती और तरीकों से लेकर उसके संबंधों, उसकी बातचीत, खाने-पीने, उठने बैठने, व्यवहार करने, आपके संपर्कों को, आपके रिश्तेदारों, मित्रों, शत्रुओं आदि सबके वृहत संग्रह के मूल्यांकन व विश्लेषण से आपकी आपकी हर गतिविधि का व्यवसायिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक उपयोग कर रहे हैं। इन सब पर दीर्घावधि से मनन चिंतन करने के उपरांत मैं यह सोचता हूं कि आखिर जिस स्तर पर यह सब कुछ किया जा रहा है।वहां तक यह धूर्त गिद्ध मक्कारों डकैतों की फौज पिछले 15 वर्षों में यह तक पहुंचे कैसे? इनकी कार्यप्रणाली का आधारभूत सिद्धांत और जिस ज्ञान और तकनीकी से इन्होंने यहां तक पहुंचने में सफलता पाई है उसके पीछे यह अंकगणित बीजगणित भाषा ज्ञान व्याकरण की आधारभूत उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई तो देखा मैंने कि यह सब जो आज यह सारी विदेशी कंपनियां इनका उपयोग कर यहां तक पहुंची है। उसके पीछे भारत की सहस्त्रों वर्षो मैं विकसित की ज्ञान भाषा व्याकरण अंकगणित बीजगणित त्रिकोणमिति लोगरिथम आदि सब इस भारत का दिया हुआ है। और उस भारत में भी यह सब श्रेष्ठता ब्राह्मण जाति के पास पाई जाती थी। तो उसे तो पूरी दुनिया पर अपनी ज्ञान की श्रेष्ठता के आधार पर राज करना चाहिए था। तो वह इतिहास के पन्नों में गरीब और भिक्षुक ब्राह्मण क्यों लिखा जाता है?

देश में पिछली तीन शताब्दियों से ब्राह्मणों को गाली देने का जो नया चलन अंग्रेजों ने ईसाइयत को बढ़ावा देने, भारतीय गुलामों को नीचा दिखाने, भारतीय ग्रंथों को, शास्त्रों, उपनिषदों, वेदो, भाषाओं में संस्कृत जो दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है, व्याकरण, हिंदी साहित्य, आयुर्वेद, अंकगणित बीजगणित त्रिकोणमिति वनस्पति, कृषि, उद्यानिकी, भौतिक, रसायन, धातु खगोलीय ज्योतिष विमानन युद्ध कला जिसमें महाभारत का परमाणु युद्ध भी है, को भारत से ले जाकर अनुवादित कर उन में आमूलचूल परिवर्तन कर अपने तरीके से ईसाइयत की श्रेष्ठता स्थापित करने और अपने तरीके से परिभाषित करने के लिए, भारत में 10लाख से ज्यादा गुरूकुलों में सभी व्यवहारिक आवश्यक विषयों की शिक्षा देने के श्रेष्ठ कार्य को करने वाले ब्राह्मणों को जो शिक्षा देकर भी,उनमें अहंकार न आ जाए, उसे वे अपनी कमाई और आय का साधन ना बना ले, उन्हीं शास्त्रों में उसको अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने की व्यवस्था निर्धारित कर दी, जो अंग्रेजों को दीर्घकाल तक भारत में शासन करने के लिए उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थी। इसलिए उन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा पद्धति को नष्ट करने लाखों ब्राह्मणों को बिना किसी कानून के चुपचाप मौत के घाट उतारा जाने लगा और 1820 तक आते-आते लाखों ब्राह्मणों की हत्या कर गुरुकुलों को चलाने के कार्य को अपने बनाए गुलामों के कानून से अवैध घोषित कर दिया। इसके लिए आवश्यक था कि ब्राह्मणों को हर तरह से बदनाम करने, भाषाई गुलाम बनाने के लिए जो आंग्ल भाषा में ज्ञान बांटने के कांवेंट अर्थात अनाथालय स्थापित किये। हो सकता है यह बात बड़े-बड़े मंदिरों के मठाधीश में छुआछूत पूजा आदि के कारण हो, फिर इन तथ्यों में सत्यता हो! पर यह सत्य भी इसलिए गले नहीं उतरता क्योंकि उन्हीं ब्राह्मणों के पास जो काशी हरिद्वार व अन्य हिंदू तीर्थ क्षेत्रों में बैठे हुए पंडित थे वही सभी जातियों के समाजों की वंशावली की लिखाई और उनकी वंशावली के दस्तावेजों को सैकड़ों शताब्दियों से सहेजते चले आ रहे थे। यदि वहां कोई जातीपांती और छुआछूत का ख्याल होता। तो वे यह कार्य केवल उच्च वर्ग के धनाढ्यों के लिए ही करते। पर यह परंपरागत कार्य सभी समाजों जातियों के लिए शताब्दियों से अभी तक करते चले आ रहे हैं।

बखूबी आज भी उसके बीज वटवृक्ष बनकर पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। इसके विपरीत लाखों वर्षों से ज्ञान बांटने और शिक्षा देने वाला सम्मानीय ब्राह्मण उसी के पढ़ाए हुए महर्षि वेदव्यास जिन्होंने गीता लिखी और महर्षि बाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी। जो दोनों ही दलित जाति के थे।

पर उनके लिखे हुए शास्त्र आज भी ना केवल भारतीय हिंदू संस्कृति को सनातन धर्म को वरन पूरे विश्व को प्रकाश स्तंभ की भांति सामाजिक रीति नीति सिखाते हुए चले आ रहे हैं। और सर्वत्र सम्मानित व पूजनीय है! आज दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस आधुनिक वैद्युतकीय तरंगों की संचार माध्यमों का मोबाइलों टीवी रेडियो आदि में उपयोग कर रही है। और पृथ्वी पर निवासरत 800 करोड़ लोगों में से लगभग 400 करोड़ लोगों से हर कदम कदम पर मोटी वसूली कर रही है। निचोड़ रही है। अपनी मोटी वसूली के लिए उसकी सांसे गिन रही है। आखिर यूरोपियन लोगों को यदि अंकगणित बीजगणित त्रिकोणमिति भौतिक रसायन का ब्राह्मणों का दिया हुआ ज्ञान नहीं होता तो क्या वे यहां तक पहुंच सकते थे और हमारे देश का यही ब्राहमण यदि अपने ज्ञान शिक्षा को अपनी बाप की जागीर या वंशजों की जागीर समझ कर सहेज कर वसूली कर रहा होता तो वह दुनिया में सबसे धनाढ्य होता। इसके विपरीत वह अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा प्राप्त कर निशुल्क नहीं बांटता होता तो यह म्लेक्ष खंड के यूरोपीय, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन कहीं गंदगी में पड़े सड़ रहे होते।

हमारे देश के जिन ब्राह्मणों का ऋषि मुनियों का पूरी दुनिया को एहसानमंद होना चाहिए था। आज वो हम से ही मोटी वसूली कर रहे हैं हमारे ही देश के लोग जिन की शिक्षा दीक्षा से आज वर्तमान में वे जहां तक पहुंचे और जीवन में जिन सुख सुविधाओं और ऐश्वर्या का भोग कर रहे हैं।

उसके पीछे क्या वह भिक्षुक ब्राह्मण नहीं जो सम्मान का पात्र भी नहीं जिसे हम 24 घंटे गालियां बकते रहते हैं। इस पर कभी किसी ने गौर नहीं फरमाया होगा। बेशक में ब्राह्मण तो नहीं। पर चिंतन मनन से मैंने यह सारे तथ्य खोजें यदि उसी ब्राह्मण ने अपनी शिक्षा दीक्षा संस्कृत व्याकरण कालगणना ग्रहों की गणना सूर्य चंद्र की परिक्रमा ग्रहण लगने की घोषणाओं से लेकर ब्रम्हांड का ज्ञान, कृषि आयुर्वेद रसायन युद्ध कला आदि तक संग्रहित कर रखा था। इसी ज्ञान को आज पूरी दुनिया उपयोग कर रही है।बेशक ब्राह्मणों के साथ छल कपट मारकाट मंदिरों की लूटपाट करने में मुगलों ने भी इस देश में लगभग पांच शताब्दी तक भारी कहर ढाया यहां तक की नालंदा जैसे विश्व विद्यालय जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ थे से 6 महीने तक मुगलों ने वहां के ब्राह्मणों के लिखे हुए सैकड़ों वर्षों के शास्त्रों की धरोहर को जलाकर भोजन बनाते रहे पानी गर्म करते रहे।

यह कोई इतिहासकार नहीं बताता क्योंकि बाद में 5 शताब्दियों तक सभी इतिहास लिखने वाले मुगलों की तलवार के नीचे उनके पक्ष में उनकी प्रशंसा के इतिहास लिखते रहे। जबकि सभी मुगल आक्रमणकारी, घोर नीच, लुटेरे, बलात्कारी, अय्याश थे। प्रशंसा का कहीं से भी कोई पात्र नहीं था। चाहे वह अकबर बादशाह हो। सब ने इस देश में हिंदुओं ब्राह्मणों सभी का घोर कत्लेआम किया। उसने सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया होता और उसके बदले में मोटी राशि वसूल कर रहा होता तो स्वाभाविक सी बात थी कि हमने और पूरी दुनिया ने उसके सामने सर झुका कर खड़े रहना था। यही कारण था कि जो अंग्रेज और यूरोप के लोग 15-16 वीं शताब्दी के पहले तक कितने ज्ञानी ध्यानी थे?

जो उन्होंने व्यापार के बहाने देश में घुसकर उनका एक समूह ब्रिटेन से बुलाकर केबल भारत के शास्त्रों का अध्ययन करना संस्कृत को समझना संस्कृत मैं लिखें शास्त्रों विविध विषयों की रचनाओं को अनुवादित करने में ही अनेकों अंग्रेजों की जिंदगियां खत्म हो गई थी और उसके तथ्यों से अपने देश को भेज कर यूरोप को परिचित करवाता रहा।

भारत के ऋषि-मुनियों के ज्ञान विज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों से सब कुछ छीन कर उस पर कब्जा जमा कर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हर तरह से उन ब्राह्मणों के प्रति छुआ-छूत के, शोषण के हिन्दुओं के समाज में वैमनस्यता के जहर के बीज बोते गए। ताकि इस देश की सच्चाई और ज्ञान विज्ञान के बारे में हमारे ही देश के लोग उन्हें गालियां बकते रहे और वे उस ज्ञान का भरपूर सदुपयोग करके पूरी दुनिया को लूटते रहे।

जैसा कि आज लूट रहे हैं।जिन ब्राह्मणों को हम देश में गाली बकते हैं वह पूरी दुनिया में अपने ज्ञान विज्ञान के कारण ना केवल पूज्यनीय है। वरन अनेकों यूरोपीय देशों में संस्कृत महाविद्यालय व विश्वविद्यालय हैं। जहां केवल भारतीय वेदों उपनिषदों पुराणों के संस्कृत में अध्ययन उसमें छुपे रहस्यों, उसकी गहराई को समझने के लिए निरंतर अनुसंधान किए जा रहे हैं। स्कूलों में गीता रामायण व अन्य संस्कृत ग्रंथों शास्त्रों की शिक्षा, अध्ययन, परीक्षाओं, प्रार्थना, पूजाओं को बचपन से ही अनेकों यूरोपीय स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है। इसके विपरीत हमारे संविधान में ही ना केवल संस्कृत वरन हिंदू धर्म की शिक्षा को संविधान के धारा 30अ के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है जो पाखंडीओं का भारतीय पुरातन संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र है। इसे हमारे ही देश वासी कब समझेंगे?

1965 के बाद बना हर कानून बहुराष्ट्रीय कंपनियों व पूंजीपतियों का

पेज 1 का शेष

इसके लिए बकायदा तरीके से अमेरिकी जालसाजों का संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाम संयुक्त शैतान संघ जो विश्व स्तर पर डब्ल्यूटीओ WTO और डब्ल्यूएचओ WHO जो कि अमेरिकी एवं यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवसायिक संवर्धन संघ है। सब पूरे पूर्व नियोजित षडयंत्र के साथ मिलकर पूरे देश और दुनिया में 6 महीने से महामारी का पाखंड फैलाकर लगभग दुनिया के 100 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा ब्रिटेन व सभी यूरोपीय देशों वाह एशियाई देशों के सभी नेता सब पूंजी पतियों से मोटा धन खाकर उनके लाभ के लिए षड्यंत्र में शामिल हैं। मात्र अपने व्यवसाय को बढ़ाने पूरे देश और दुनिया में अपने मकड़जाल को फैला कर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की वैक्सीन जो दुनिया के लोगों को नपुंसक बनाकर आबादी को खत्म करना चाहती है। दुनिया के लोगों को गुलाम बनाने उनके मस्तिष्क में चिप फिट करके अपने तरीके से उन भेड़ों को नचाने का षड्यंत्र रच रही हैं। ताकि उनकी मर्जी के बिना न वो शादी करें। संभोग भी ना कर सके। और बच्चे भी पैदा ना कर सकें। और देश और दुनिया की उपजाऊ जमीनों पर इनका कब्जा हो और यह अमरफल खाए हुए महा धूर्त, घोर नीच, चांडाल मानव राक्षस हजारों साल धरती पर एकछत्र राज्य कर सकें। बात थोड़ी गहरी और लंबी है। फिर भी आसान भाषा में लिखी गई है।

इसलिए देश दुनिया का मीडिया पिछले 6 महीनों से कोरोनावायरस का पाखंड फैलाकर देश और दुनिया की जनता में दहशत फैला कर उसको मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर कर स्वंय आत्महत्या कर लेना या बेरोजगारी और भूख से तड़प कर घुंट घुंट कर मर जाने के लिए विवश करने का षड्यंत्र है। मीडिया का 24 घंटे करोना की महामारी का पाखंड फैलाना और दहशत बांटना। देश और दुनिया की जनता के लिए आवश्यक है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस पाखंड मैं चुरकट देश दुनिया की कठपुतली सरकारों को नचाने जनता में भय पैदा करने और उन्हीं उसी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों द्वारा मार डालने के षड्यंत्र के खिलाफ सड़कों पर उतरना ही होगा।इसको जनता समझे। मेरी हर बात की सच्चाई थोड़े समय के बाद समय सामने आ जाती है।

यह आप पिछले 5 महीने से लगातार देख रहे हैं। और मेरे समाचार पत्र को व मुझे पढ़ने वाले 20 साल से मेरे लिखे हर सच को पूर्ण होता हुआ देख रहे हैं।

साप्ताहिक समय माया

उद्यानिकी विभाग में भी चल रहा लूट का तांडव

प्रधानमंत्री योजनाओं और राज्य की योजनाओं में सीधे उत्पादक, आपूर्तिकर्ताओं डीलर और वितरण के खाते में भुगतान करवा कर किया जा रहा भ्रष्टाचारके खातों में उद्यान की विभाग में राज्य योजनाओं में फल क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, सब्जी क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना, घरेलू बागवानी की आदर्श किचन गार्डन योजना, औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार, कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम, प्रदर्शनी मेला प्रचार प्रसार योजना, मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना, केंद्र की योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय औषधीय पौधे मिशन, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं आदि योजनाओं में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी की फसलों जिसमें सब्जी, फल, फूल, मसाले, औषधीय उत्पादन हेतु पर्याप्त अनुदान दिया जाता है, यह अनुदान जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना फव्वारा खेती परियोजना, ग्रीन नेट, शेडनेट, आदि में पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। इसमें वहां बैठे तकनीकी बाबू से लेकर सहायक संचालक उपसंचालक तक किसानों को जो अनुदान की सुविधाएं मिलती हैं। उसमें मोटी वसूली करने के बाद ही वह सुविधाएं दी जाती हैं। जो कि अधिकांश था कागज पर ही पूरी हो जाती हैं। स्वाभाविक सी बात है किस प्रकार सही किसानों से अनुदान के नाम पर हर क्षेत्र में मोटी वसूली इंदौर उज्जैन संभागों के सभी जिलों के साथ पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही है। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है किस पूरे विभाग में बरसों से ना तो नई भर्तियां हुई है नाही नई नियुक्तियां और ना ही पदोन्नतियां की गई हैं। जिसकी आड़ में विभाग के कार्य को संचालित करने के लिए उद्यान पर उद्यान प्रभारी को सहायक संचालक और उन संचालकों के पद पर बैठा कर प्रभार के पद पर बैठा के समय ही मोटी वसूली कर ली गई थी और बाद में उनको उस पद पर बने रहने के लिए मासिक भुगतान भी संचालक प्रधान सचिव के साथ वहां के जिलाधीश संभाग आयुक्त के साथ वहां के सांसद विधायकों से लेकर गांव के सरपंच तक का भुगतान करना पड़ता है इसलिए भ्रष्टाचार यदि विभागीय कर्मचारी अधिकारी ना करें तो वे उस पद पर वहां बैठ नहीं सकते इसलिए अधिकांश योजनाओं में जो ऊपर दर्शाई गई हैं हर कदम पर भारी भ्रष्टाचार होता है और पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में यह भी हुआ एक कर्मचारी के नाम से योजनाओं का पैसा निकल गया क्योंकि 50% अनुदान था और 50% से लेकर 70% तक उसमें बैंक का जिसे ग्रीन लाइट शेड नेट माइक्रो इरिगेशन के लिए कुंए बिजली कनेक्शन आदि का भुगतान किसानों के नाम से हो गया परंतु किसानों को उसका एक पैसा हाथ में नहीं आया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में फव्वारा खेती और टपक सिंचाई में इंदौर में ही सन 2000 के बाद में भारी भ्रष्टाचार हुआ कई किसानों को उसका पैसा नहीं मिला जिसकी जांच आज तक लंबित है इस प्रकार से शासन की अच्छी योजनाओं में यदि तरीके से काम होता तो ना केवल सब्जी फल फूल मसाले औषधि वनस्पतियों का उत्पादन ना केवल किसानों के खेत में बल्कि शहरी क्षेत्र के रहवासियों को उनके घरों में रसोई की सब्जियों व मसालों के लिए भी पर्याप्त बीज पौधे व अन्य सुविधाएं केंद्र व राज्य शासन ने उपलब्ध करवाई थी परंतु भारी भ्रष्टाचार के कारण उसका पर्याप्त लाभ ना शहरी क्षेत्र की आबादी को मिला और ना ही उद्यानिकी से संबंधित उत्पादन के लिए गांवों के किसानों को मिल रहा है। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती तो शासन की अपनी उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत अपनी पौधशाला अंजू थी जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन हर जिले की पौधशाला में जहां पर फल फूल व अन्य उद्यान के उत्पादन के बाग व रोपनी हैं। उनके उत्पादन की नीलामी में भी भारी भ्रष्टाचार होता है यहां तक कि इंदौर के फल बाग व अन्य आरोपियों की जमीनों के हेरफेर के साथ इंदौर की अनेकों रूप नींव में तो बड़े बड़े गुंडे मवाली और नेताओं ने अपनी कालोनियां काटकर मोटा पैसा विभाग के अधिकारियों के साथ हजम कर लिया। जिसकी जांचें हर स्तर पर लंबित होने के बाद में उनमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई यही हाल धार की कुक्षी मनावर की रोशनी हमें भी हुआ जहां पर वहां पर बैठे उद्यान की प्रभारियों ने रोपणीयों की जमीनों को ही अपने खास मित्रों को ठेकेदारी में हवाले करने की शिकायतें होने के उपरांत भी जबकि उसके बारे में अनेकों पत्रकारों ने ना केवल धार कलेक्टर जिला पंचायत धार उद्यानिकी विभाग धार के साथ इंदौर के संभाग आयुक्त, भोपाल में बैठे प्रधान सचिव और संचालक उद्यान की को करने के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भी की। उसके इन कांडों के बारे में जानकारी मांगी गई पर सब भूखेरे श्वानों ने जानकारी देने की अपेक्षा उल्टे सीधे पत्र देकर सारी शिकायतों को और उस पर क्या कार्रवाई की गई जानकारी देने से साफ मना कर दिया अर्थात भ्रष्टाचार को उद्यानिकी विभाग में संरक्षित करने के लिए उद्यान प्रभारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक सब कुंडली मारे बैठे हुए हैं।यह कहानी ना केवल उज्जैन इंदौर संभाग के 15 जिलों की है वरन मध्य प्रदेश के 51 जिलों और पूरे देश के 680 जिलों की है।

मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग मैं बरसों से बैठे है बड़े अधिकारी

तालाबंदी के समय में आयुक्त ने किशोर वाधवानी से 18 बार बात की थी आज तक कोई जांच नहीं

अधिकारी अपनी उपस्थिति पत्रक पर नहीं करते हैं हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के अधिकांश वाणिज्य कर वृतों में और संभागीय कार्यालय में वर्षों से अधिकारी एक ही स्थान पर बैठे हैं। जो वैसे तो मसक कानून की लगने के बाद क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होने लगा है। इसलिए वसूली की संभावना काफी हद तक कम हो चुकी है।

इसके विपरीत वर्षों से सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त और उपायुक्त के रूप में 100 से से ज्यादा अधिकारी एक ही स्थान पर सेवा चाकरी के बाद जमे हुए हैं, जबकि हर अधिकारी का अनिवार्य रूप से 2 साल या 3 साल के बाद स्थानांतरण हो जाना चाहिए पर अधिकांश महिला अधिकारी पांच 5 वर्षों से ज्यादा समय से कई 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से इंदौर में ही जमी हुई है। स्वभाविक है, पुरानी वसूली में पुरानी वेट के खातों में जो अभी तक करारोपण कै असेसमेंट कि जो पुरानी मामला अभी तक लंबित है उनमें अभी तक हजारों करोड़ की वसूली इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के कारण रुकी हुई है।

वह जानबूझकर वकीलों के साथ मिलकर करों मैं छूट देते रहते हैं। और उस प्रकार से सन 1959 से लेकर सन 30 जून 17 तक के पुराने करारोपण के खातों में हजारों करोड़ की वसूली इसलिए लंबित पड़ी हुई है। कई स्थानों पर तो करदाता की संपत्तियां विभाग ने सलंग्न करने के बाद में भी उनकी वर्षों से नीलामी स्थगित होती रही हैं। वह पैसा भी अटका हुआ है। जानबूझकर एक ही अधिकारी कर्मचारी 10 साल से ज्यादा समय तक बैठा रहेगा। स्वामी सी बात है सरकार को राजस्व की मोटी हानि हो रही है। वैसे भी जब जिसको जहां मौका मिले हाथ मार ले कल किसने देखा है। इसी तरह से जब देश भर में तालाबंदी का पाखंड चल रहा था।

तब यहां का सांसद शंकर लालवानी जो किशोर वाधवानी का साझेदारी बताया जाता है। उसके गुटके को बिकवाने के लिए जैसा कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर एजेंसी के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच में पाया की इंदोर का कलेक्टर मनीष सिंह ने किशोर वाधवानी इसके साथ में बात करके उससे 180 कॉल किए और उसका कि लगभग 7000 करोड रुपए का असली नकली गुटका सिगरेट आदि का व्यवसाय पूरे देश में ब्लैक में करवाने के लिए उसके सभी वाहनों को आने जाने की पूरी छूट दी इतने बड़े कांड में घोर ऐतिहासिक भ्रष्ट मनीष सिंह को चूंकी शिवराज ने अपनी वसूली के लिए बैठाया था। इतनी बदनामी होने के बाद में ना तो उसे हटाया और यही हाल मध्य प्रदेश वाणिज्य कर के आयुक्त राघवेंद्र सिंह का हुआ उन्होंने भी उसके गुटके के लिए उससे 18 बार बात की। जैसा कि सभी समाचार पत्रों ने देश और प्रदेश में छापा था। ना ही मनीष सिंह को हटाया गया और ना ही कर आयुक्त राघवेंद्र सिंह को हटाया गया। अर्थात जिसको जहां मौका मिले वसूली कर ले अन्यथा कल किसने देखा है ऑफिस तालाबंदी के समय में तो सभी अधिकारी तानाशाह बन कर अपने तरीके से अपनी मोटी वसूली करते हुए अपने सारे भ्रष्टाचार को खुले में अंजाम देने पर लगे हुए थे।

वैसे तो देशभर में यथार्थ में कोई बीमारी नहीं। सारी बीमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सारे देश का व्यवसाय समाप्त करने का षड्यंत्र था। इसलिए केंद्र सरकार के पहली तालाबंदी खुलने के बाद 18 मई से देशभर में सारे ट्रक जो शॉपिंग माल वालों के थे, दौड़ने लगे थे और शॉपिंग मॉल वालों को लगातार सप्लाई मिल रही थी। परंतु वह शॉपिंग मॉल वालों को छूट देने और उनसे मोटी वसूली करने के लिए जानबूझकर मध्य प्रदेश वाणिज्य कर को 18 मई से 20 जून तक उसके एंटीइवेजन ब्यूरो को भी जांच करने और पकड़ने का अधिकार नहीं दिए थे। ताकि सत्ता के और इनको भ्रष्ट भारतीय प्रताणना सेवा के अधिकारियों को जो जिलाधीश और आयुक्तों के रूप में बैठे हुए हैं। इनकी मोटी कमाई होती रहे और अभी भी यह सिलसिला चल रहा है। जानबूझकर दो दो तीन तीन अधिकारियों को ही जांच करने ट्रकों को पकड़ने और कर चोरी को रोकने के लिए अधिकार दिए जाते हैं। पूरे अधिकार ना बोलने से जबकि बाजार पूरा खुल चुका है। स्वाभाविक सी बात है। कि जानबूझकर बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जिसकी केंद्र और राज्य सरकारें कठपुतली बनकर नाचते हैं और जिनके लिए देश में 6 महीने का ताला बंदी का षड्यंत्र रचा गया था। पूरी छूट दी जा रही है।

छोटे व्यापारियों को तो जीएसटी के अत्यधिक उलझन पूर्ण कर प्रणाली में उलझा कर वैसे ही व्यवसाय बर्बाद किया जा रहा है। 1 जुलाई 17 से देश पर पूंजी पतियों के मोटे लाभ और भारी कर चोरी के लिए उनके इशारे पर थोपे गए माल एवं सेवा कर के 2 साल गुजर जाने के बाद में भी नाही जीएसटी काउंसिल के साथ केंद्रीय कस्टम और एक्साइज का जीएसटी कर विभाग इसको समझ सका है। और ना सभी राज्यों के करा आयुक्तों से लेकर वहां के अधिकारी कर्मचारियों के साथ कर सलाहकार ही नहीं समझ सके तो बेचारे व्यापारी कैसे समझ सकेंगे उस में उलझा कर उन पर जानबूझकर भारी करारोपण कर वसूली कर बर्बाद किया जा रहा है।

सूचना के अधिकार में जब चारों तरफ महामारी का तांडव फैला हुआ था सरकारी एजेंसियां मोबाइलों मीडिया और चौबीसों घंटे टीवी समाचार चैनलों पर भारी दहशत बांटकर लोगों को भयभीत कर मानसिक रूप से कमजोर बीमार और मृत्यु का महोत्सव मना रही थी। यही कारण था इसके अंतर्गत जानबूझकर सूचना के अधिकार में अधिकारियों और कर्मचारियों के उपस्थिति पत्र की फोटो कॉपी मांगी गई थी ताकि कर्मचारी और अधिकारी घरों के दहशत भरे बातावरण से निकलकर अपने कार्यालयों को पहुंचकर मित्रों में बैठकर भले ही काम करें ना करें पर कार्यालय में आकर अपनी दहशत दूर कर सकें। पहली बार मालूम पड़ा कि कोई भी अधिकारी उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं करता है उसे मध्य प्रदेश सरकार से ही छूट मिली हुई है। तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालय में आकर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता। आखिर उसे भी जनता के धन से वेतन मिलता है और अपनी उपस्थिति वह कार्यालय की पंजी पर दर्ज क्यों नहीं करवाता। आखिर सामान्य प्रशासन विभाग ने हीं अधिकारियों को यह छूट क्यों और कैसे दे रखी है?

आखिर भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी भी जनता के धन से वेतन लेते हैं उन्हें भी अपने कार्यालय में आकर अपनी उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने ही चाहिए। ठीक है वह अपने आप को देश का भाग्य विधाता समझता है। पर है तो सरकारी नौकर और नौकर है, तो उसे हस्ताक्षर करना ही चाहिए चाहे वह जिले का जिलाधीश हो या मंत्रालय में बैठने वाला प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी अपने बाप की जागीर नहीं है देश की सत्ता और जनता का धन जिसके लिए वह जवाब देह नहीं।

जबकि केंद्रीय विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उपस्थिति पत्रक पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तत्काल सरकार को चाहिए कि सभी अधिकारियों को उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए साथ ही जो अधिकारी वर्षों से एक ही स्थान पर कुंडली मारे बैठे हैं और जिनकी 3 साल से ज्यादा एक ही स्थान पर पदस्थ ही हो चुकी है उन्हें तत्काल जिले से बाहर 300 किलो मीटर दूर स्थानांतरण करना चाहिए।

बेशक हर विभाग के मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह मोटी कमाई का साधन बन जाएगा परंतु नियमों का पालन भी आवश्यक है ताकि सारे कर्मचारी और अधिकारी जो एक ही स्थान पर वर्षों से जमे हुए हैं उनका जलवायु परिवर्तन होने से कान की उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी नए स्थान पर नए लोगों से मिलना जुलना होगा तो स्वभाविक सी बात है तरोताजा की आएगी और काम करने में भी मन लगेगा एक ही स्थान पर बैठे रहने से अधिकारी कर्मचारी मट्ठर और उनके मस्तिष्क कुंद हो जाते हैं। जिससे उनकी कार्यकुशलता पर भी भारी असर पड़ता है।

न रोजगार, न व्यापार, कोई प्रोत्साहन नहीं, शासकीय विभागों, उपक्रमों को लूट व लुटाकर करो बंटाधार

देश का बजट, औपचारिकता और वाचालता, अर्थव्यवस्था की बर्बादी

देश के आर्थिक सुदृढ भविष्य की समृद्धि का विचार हीनबजट 2020 था। जो अज्ञानीयों, अनपढ़, पूंजी पतियों की रखैलों ने पूंजीपतियों के इशारे उनके लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण तरह से बर्बाद करने यथार्थ में केवल बजट की औपचारिकताएं पूरी करना केवल बाचालता से भरा हुआ था। नोटबंदी ने लोगों के साथ उद्योगों व्यापारियों से लेकर बड़े-बड़े उद्योगो में नगदी की कमी के कारण एक तरफ 80 करोड़ से ज्यादा मध्यमवर्गीय गरीब लोगों में क्रय क्षमता कम होने के कारण मांग खत्म हो गई, को जागृत करने के लिए आवश्यक था, की सरकार सबसे पहले आयकर की सीमा को न्यूनतम 5लाख करती और 5लाख से 10लाख तक केवल 10% आयकर करती।

ताकी ज्यादा धन बाजार में आता, जनता बाजार में खरीदारी करती और खरीदारी बढ़ती तो औद्योगिक उत्पादन की मांग बढ़ती जिससे उद्योगों को जीवनदान मिलता, उद्योगों की उत्पादन क्षमता और रोजगार बढ़ाये जा सकते थे।

मोदी का बजट 2020 स्वयं ही ना तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्पष्ट है ना ही वित्त मंत्री सचिव ना स्पष्ट रोजगार की बात है। ना ही औद्योगिकरण, देश की सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे से लेकर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च तकनीकी शिक्षा आदि के संबंध में कोई स्पष्ट बजट का आवंटन की बात नहीं है। जो भविष्य में देश की आर्थिक प्रगति को निश्चित करेगा। साथ ही यही सब भविष्य में भारत के 20 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ठोस और दीर्घकालिक स्थाई रोजगार दे सकेगा।

बजट में एक अरब करोड़ रुपए की व्यवस्था अवश्य की गई है। परंतु उसके संबंध में भी नीतियां कोई भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अधिकांश नई सड़कें या राष्ट्रीय राजमार्ग या तो बी ओ टी या लोक व निजी साझेदारी के अंतर्गत बनाई जा रहे हैं या लोक निजी साझेदारी में बनाई जाकर अधिकांश पर जबकि वाहनों पर 28% जीएसटी जिसमें 14% राज्यों का और 14% केंद्र का है।

वसूलने के बाद पेट्रोल पर भी 80₹ तक और राज्यों का और केंद्र का करारोपण होने के उपरांत भी वाहन पंजीयन के समय भी राज्यों का 10 से 15% तक मार्ग शुल्क वसूलने के उपरांत भी जनता को पूरे देश में सड़के निशुल्क को नहीं दी जा रही।

बेशक इस कहानी का सबसे बड़ा सड़क माफिया स्वयं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ही है जिसकी देश के अंदर लगभग राष्ट्रीय राजमार्गों की बीओटी 50% ज्यादा सड़कों में साझेदारी है। या उसके स्वयं के हैं जहां सड़कों के ठहराव पत्र पर हस्ताक्षर करने पशु करने पर ही वसूली शुरू कर दी गई थी सड़कों के पूरे ढंग से बनने की बात तो बहुत दूर दूसरी तरफ अधिकांश राज्यों की और केंद्र की टोल सड़कों पर रखरखाव उचित तरीके से हो ना हो। परंतु वाहन चालकों से वसूली प्रति किलोमीटर के हिसाब से नहीं वरन बैंक से लिए गए ऋणों के भुगतान के अनुसार की जा रही है जबकि मूल सड़क की लागत से 3 गुना ज्यादा पर डीपीआर बनाकर जिसका 25% तक केंद्रीय मंत्री व वहां के पांच विभागों के मुख्य सचिवों तक पैसा बट जाता है जो प्रति किलोमीटर तीन से चार करोड़ रुपए तक होता है लूट की जाती है यही कारण है कि कई सड़कें तो बनाना शुरू करने के साथ ही उस पर टोल वसूली शुरू कर दी गई थी जबकि सर के 10 वर्ष होने के उपरांत भी अभी तक पूर्ण सही तरीके से स्तर की उपलब्ध नहीं हो हो रही है।

यही हाल उच्च तकनीकी स्वास्थ्य अभियंत्रिकी प्रबंधन आदि की शिक्षा का भी है यहां भी सरकार स्वयं अपने संस्थान नहीं खड़े करेगी वरुण यहां पर भी लोक निजी साझेदारी में ही सारे प्रस्तावित शिक्षा संस्थान जनता को लूटने के लिए ही खड़े किए जाएंगे। वैसे तो मोदी का पूरा बजट ही भ्रम पूर्ण स्थिति में है जहां देसी निवेशकों को शक्ति के साथ हतोत्साहित किया गया है वहीं विदेशी निवेश को छुटों के साथ प्रोत्साहित किया गया है जो कि दीर्घावधि में देश की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्त्रोतों पर अपने भारी लाभ के चलते अधिग्रहित करने में सक्षम हो जाएगा इसके विपरीत होना यह चाहिए था आयकर और दूसरे अन्य करो मैं सरकार को अपनी वसूली शिथिल करके घरेलू बचत को बढ़ावा देकर घरेलू निवेश को बढ़ावा देना चाहिए था बेशक यहां अप्रत्यक्ष ख्याल यह भी हो सकती है कि जो देश से रुका हुआ धन विदेशी पूंजी पतियों के या उनके नाम से घूम कर पुनः भारत में ही उन्हें निवेश कर दिया जाएगा जिस पर उनकी मोटी वसूली और लाभ प्राप्त किए जाएंगे जैसा कि गुजराती माणूसों का पुराना ऐतिहासिक हथकंडा रहा है।

इस बजट में भी सरकार ने कांग्रेश के बनाए और खड़े किए हुए सार्वजनिक उपक्रमों जिसमें बैंकिंग सेक्टर की सारी बैंक्स औद्योगिक व संरचना निवेश जिसमें औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई भारतीय साख एवं औद्योगिक निवेश जैसे आईसीआईसीआई एचडीएफसी बीमा सेक्टर की भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य बीमा कंपनियां तेल कंपनियां धातु कंपनियां संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड महानगर टेलीफोन रेलवे सड़कें हवाई अड्डे आदि को पूर्ण रूप से अपने स्वामित्व में रखने, अधिक लाभप्रद और मजबूत बनाने की अपेक्षा, अपनी पूंजीपति मित्रों अदानी अंबानी टाटा बिरला व अन्य को मोटे कमीशन पर पट्टेपर देकर, बेचकर, कोढ़ियों के भाव लुटा कर धन इकट्ठा करके विदेशों में मौज मस्ती करने के लिए जैसे पिछली सरकार में 95 से ज्यादा विदेश यात्राओं में, मैजिक मोदी में लगभग 90 लाख करोड रुपए बर्बाद किया गया और जीतने के बाद अकेले अमेरिका में ही हावडी मोदी में डेढ़ लाख करोड डॉलर अर्थात 108 लाख करोड़ को बर्बाद किए गए।

वाचाल भेडिये मोदी ने, सत्ता को और देश की अर्थव्यवस्था को अपने बाप की जागीर मानी अपनी मौज मस्ती और अपने गुजराती ठाकुरों को लुटाने के लिए पूर्ण रूप से जनता को निचोड़ कर और बर्बाद कर अर्थव्यवस्था की स्तर पर तबाही कर रहा है पर मोदी के अंध भक्तों को इससे कोई मतलब नहीं यथार्थ में मोदी के आने के बाद से केवल गिने-चुने 1520 उद्योगपतियों को मोटा लाभ करवाने दिलवाने देश की संपत्तियों को उनके हाथ सौंपने मोटा कमीशन वसूल कर देश की आधारभूत शासकीय सेवा प्रदाता कंपनियों तेल विपणन कंपनियों उत्खनन संचार आदि को तबाह कर जिसमें रेलवे बैंकिंग बीमा बीएसएनएल एमटीएनएल डाक विभाग स्वास्थ्य शिक्षा आदि के करोड़ों कर्मचारियों को बेरोजगार कर कर उनकी संपत्तियों को भी उन्हें पुणे दामों में मोटा कमीशन हजम कर बर्बाद किया जा रहा है मोदी का 6 सालों में कोई भी बजट बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से जनहित में देश के आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए नहीं किया जा सका।

स्वाभाविक था जनता के पास क्रय क्षमता के बढ़ने से जनता ज्यादा खरीदी करती उद्योग ज्यादा उत्पादन करतेयुवाओं को रोजगार मिलता बदले में भले ही सरकार को आय कर कम मिलता तो भी एक्साइज कस्टम के साथ ही एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी में कई गुना बढ़ोतरी होती।

परंतु यह तो केवल 45-50 उद्योगपतियों का पेट भरने का ही उद्देश्य हो तो और बाकी सब को खत्म करने अत्यधिक उलझन पूर्ण जिसे स्वयं सरकार के लागू करने वाले महा धूर्त भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी ही ना समझ पाए हों, तो विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या खाक समझेंगे। दूसरी तरफ जिन व्यापारों को जीएसटी भरना है उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा यहां सवाल बिक्री पर विक्रय कर या माल एवं सेवा कर वसूलने का नहीं था यह तो सवाल इस अतिरिक्त पेचीदा माल एवं सेवा कर लगने का उद्देश्य ही था कि छोटे एवं मध्यम वर्ग व्यापारियों को प्रपंचों में उलझा कर उसके व्यापार को चौपट करो और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करें व्यापार बंद ना करें तो कर प्रपंचों में उसे जेल की हवा खिलवाओ।

इसकी दूसरी तरफ बड़े जाल साज पूंजीपति उद्योगपति जानबूझकर उसने उन करो कि पेचीदा भाषा में सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को उलझा कर खुद मनमानी टैक्स चोरी करते रहो और उसके बदले में मोटा लाभ कमाने के साथ सस्ती कीमत पर माल बेचकर छोटे व्यापारियों उद्योगपतियों जो जीएसटी लागू होने के बाद से लगभग 50 लाख से ज्यादा उद्योग और एक करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारियों को इसी चक्कर में उड़कर अपना कारोबार बंद कर छोटे-मोटे नगदी के व्यापार करने पड़े वह भी एक बड़ी बेरोजगारी का कारण बना पर इससे इन मोर घोर लालची मक्कार गुजराती सूकरों को क्या फर्क पड़ने वाला है। इनके पास तो इनके तिजारा का ही जो है वहीं के माई बाप और भगवान हैं इन्हें देश के 135 करोड़ जनता से कोई मतलब नहीं।

जो आर्थिक सामाजिक कर चुका है। अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में पहले रिजर्व बैंक को 40 लाख करोड़ से उसके साथ स्टेट बैंक व अन्य 29 सरकारी बैंकों कोनिचोड़ने के बादभारतीय जीवन बीमा निगम को लूटने के लिए उसके बाजार में शेयर पूंजी के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ वसूल करने की तैयारी करी की जा रही है इस घोर अधम नीच गुजराती भूखे अमित शाह और मोदी के पास भविष्य का कोई दर्शन नहीं देश की समृद्धि और आर्थिक सुदृढ़ता की आधार बैंकों को डुबोया।

1990 के बाद विश्व व्यापार संगठन बनाम विश्व व्यापार आतंकी संगठन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लेने के लिए जो समझौते लागू किए थे। उसके चक्कर में देश में ना केवल केंद्रीय वरन राज्यों की सरकारों ने भी अपने करीब 1 सौ से ज्यादा विभागों में भर्तियां नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप सभी विभागों में समय तकनीकी और योजनाओं के चलते कार्य 4 से 10 गुना ज्यादा हो गया। तो 1990 की तुलना में और 2020 तक आते-आते 70 करोड़ की जनसंख्या 132 करोड़ हो गई परंतु कर्मचारियों और अधिकारियों के अभाव में एक तरफ भ्रष्टाचार में लूटपाट बड़ी तो दूसरी तरफ समय के बदलाव के साथ काम का बोझ बढ़ने कार्य करने में पेचीदगियां भी बढ़ीं।

पर स्टाफ नहीं बढ़ाया गया। जहां कर्मचारियों अधिकारियों कीसंख्या बढ़ाई भी गई तो पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास से लेकर कार्य विभाग यथा लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जल संसाधन ग्रामीण यांत्रिकी, विद्युत मंडल, गृह निर्माण, नगर पालिका, निगम, परिषदों, जनपद, पंचायतों, जिला पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायतों तक में संविदा कर्मियों की नियुक्तियां, सुरक्षा,सैनिकों को दैनिक वेतन भोगियों जो छोटे बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला तकनीशियन, पदों से लेकर तकनीकी विभागों में इंजीनियरों, डॉक्टरों, विषय विशेषज्ञों में प्राध्यापक तक की भर्ती संविदा कर्मियों के स्तर पर रुपए 300 से लेकर रुपए 500 प्रतिदिन के भुगतान पर 9000 से लेकर पंद्रह रुपए 20000 तक के अधिकतम वेतन पर कि जाकर केंद्रीय व राज्य के समस्त विभागों में काम चलाया जा रहा है।

स्वाभाविक सी बात है यह संविदा कर्मी है मौका मिलते ही दोनों हाथों से बटोर कर भारी भ्रष्टाचार कर आराम से शासकीय योजनाओं कार्यों कि बर्बादियों में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ऊपर बैठे भारतीय प्रताणना सेवा के अधिकारी, युवा और युवतियों का भरपूर तन मन धन से शोषण कर रहे हैं। जबकि सरकार चाहे तो लगभग केंद्र व राज्यों के सभी विभागों में एक करोड़ से ज्यादा खाली पड़े हुए पदों पर भर्ती देकर जो वेतन बाटेगी उससे उन लोगों का जीवन सुधारने के साथ देश की जनता की क्रय क्षमता मैं बढ़ोतरी होने से शासन को दूसरी तरफ करो में भी बढ़ोतरी होगी। उत्पादन बढ़ने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो देश की समृद्धि में काम आएगा परंतु धूर्त मोदी अमित और उनकी वित्तीय मंत्री सीतारमण की सरकार को इन सब से कोई मतलब ही नहीं रहा। केबल इस पार्टी का जो चरित्र रहा है लंबी चौड़ी लच्छेदार गप्पों को चुटीले अंदाज में प्रस्तुत कर स्वास्थ्य कर्मचारियों अधिकारियों शासन को और जनता को भ्रमित करना इस बजट में सीतारमण ने लंबे भाषण देकर यही किया।

भारत को दुनिया का उत्पादन केंद्र बनाओ

पेज 1 का शेष

खिलौने वस्त्र औषधि स्वचालित वाहनों के निर्माण, एवं उसके कल पुर्जों के निर्माण से लेकर रक्षा संसाधनों तक के सारे सामानों का उत्पादन अपने देश में बढ़ाकर पूरी दुनिया में निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हो चुका है। उसके लिए अपने उत्पादन को पूरी दुनिया में बेचने के लिए अब सारे रास्ते सारे देश उनके बाजार स्वतंत्रता से बिना किसी सस्ते माल के प्रतियोगी विक्रेता के उपलब्ध हैं। भारत में भी सस्ता, शिक्षित, तन्मयता से उत्पादन करने वाला श्रम, सस्ता कच्चा माल, सस्ता प्रबंधन, प्रचूर विद्युत, जल एवं भूमि उपलब्ध है। कोरना की आड़ में चीन को चारों तरफ भयंकर पटकनी देकर उसे सभी क्षेत्रों मैं उत्पादन कर उससे बेहतर विश्वसनीय अच्छी गुणवत्ता का माल पूरी दुनिया में आपूर्ति कर अपनी अर्थव्यवस्था को पांच अरब करोड़ कि अपेक्षा 50 अरब करोड़ की बना सकता है। मोदी को देश की अर्थ व्यवस्था को अपने कृषि उत्पादन के साथ औद्योगिक उत्पादन को हर क्षेत्र में विकसित कर तत्काल इस लाभ का फायदा उठा पूरे देश की बेरोजगारी को दूर कर मजबूत बना लेना चाहिए।

साप्ताहिक समय माया

जिला पंचायतों में चल रहा भारी भ्रष्टाचार

वहां वर्षों से कुंडली मारे बैठे अधिकारी कर्मचारी घोर ढीठ, भ्रष्ट और मक्कार

हर योजना में छाया है भारी भ्रष्टाचार 60% तक पैसा हो जाता है हजम

प्रदेश की ओर देश की सभी जिला पंचायतों में जो ग्रामीण विकास शिकारियों की 84 से ज्यादा योजनाएं जिनकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों की होती है। यथार्थ में सब वसूली में लिप्त रहकर गांव के सरपंच सचिवों रोजगार सहायकों को खुली छूट देकर लूट करवा कर अपनी वसूली करते रहते हैं यही कारण है कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर गांव के सरपंच सारे तांडव करने के बाद में भी हर बात की जानकारी को निरंतर कर देते हैं जैसे इनके बाप की जागीर हो चुकी के ऊपर जितने भी जिला पंचायत में कर्मचारी व अधिकारी बैठे होते हैं अधिकांश सभी संविदा कर्मी होने के कारण सबको लूट में ज्यादा विश्वास होता है क्योंकि उन्हें मालूम है ज्यादा से ज्यादा सरकार हमारे भ्रष्टाचार को पकड़ लेने के बाद हटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए छुट्टे होकर चारों तरफ अपनी वसूली पर केंद्रित होकर सारे काम करते हो करवाते रहते हैं। यही कारण की धारा 4 मैं सारे विभाग के सारे धन के आवंटन और उसके उपयोग की जानकारी अभी तक पंचायतों से लेकर जिला पंचायतों के बैठे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हर कदम पर सारी योजनाओं में उनकी स्वीकृति में जिसमें खासतौर से मध्यान्ह भोजन ग्रामीण विकास, शिक्षा, सड़कों के निर्माण, पेयजल व्यवस्था,

14 वॉ वित्तय आयोग (52)
14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस ग्रांट) (85)
15 वां वित्त आयोग (15thFC) (107)
बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (BRGF) (11)
मुख्य मंत्री हाट बाजार योजना (12)
ई-कक्ष निर्माण हेतु प्राप्त राशि (47)
पंचायत भवन निर्माण हेतु प्राप्त् राशि (6)
गौण खनिज (82)
मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (88)
पंच परमेश्वर योजना (68)
पंचायत सशक्तिकरण एवं जबाबदेही प्रोत्साहन पुरुस्कार योजना (22)
परफोरमेंस ग्रांट - राज्य स्तर (सिंहस्थ विशेष) (73)
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (74)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (81)
राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरुस्कार (23)
ग्रामीण विकास विभाग - मनरेगा (8)
आर.जी.पी.एस.ए. -पंचायत भवन मरम्मत (46)
स्टाम्प शुल्क (राज्य स्तर) (76)
राज्य वित्त आयोग / मूलभूत (7)
राज्य वित्त आयोग - जनपद पंचायत स्तर (10)
राज्य वित्त आयोग - जिला पंचायत स्तर (9)
ग्राम सभाओं का सुदणीकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण (60)
स्वकराधान प्रोत्साहन योजना (13)
ग्रामीण विकास विभाग - एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र मिशन IWMP (53)
ग्रामीण विकास विभाग- बुंदेलखंड क्षेत्र विकास (31)
ग्रामीण विकास विभाग - आई. ए.पी योजना (26)
ग्रामीण विकास विभाग - इंदिरा आवास योजना (36)
ग्रामीण विकास विभाग - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचिन शेड निर्माण (27)
म.प्र. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज्य रुरबन मिशन (100)
निर्मल ग्राम पंचायत पुरुस्कार की राशि (49)
निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--सामुदायिक शौचालय (54)
निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--व्यक्तिगत शौचालय (18)
निर्मल भारत / स्वच्छ भारत अभियान--शाला शौचालय (17)
स्वच्छ भारत मिशन (87)
तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रवंधन (93)
जिला योजना मण्डल (91)
DSMA (94)
जनभागीदारी योजना (21)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (92)
म. प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति (90)
महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी भवन निर्माण (28)
महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी बाउण्ड्रीवाल निर्माण (55)
महिला एवं बाल विकास-आंगनवाडी शौचालय निर्माण (29)
शिक्षा विभाग - सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना (61)
शिक्षा विभाग - छात्रावास भवन निर्माण (63)
शिक्षा विभाग - माध्यमिक शिक्षा मिशन (16)
शिक्षा विभाग - सर्व शिक्षा अभियान (15)
शिक्षा विभाग - शालाओं में बाउण्डी वॉल का निर्माण (62)
शिक्षा विभाग - शालाओं में शौचालय का निर्माण / मरम्मात (56)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना (65)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - ग्रामीण नलजल योजनाओं का संधारण (64)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - हैंडपंपों के क्षतिग्रस्तस प्लेट फार्म का निर्माण (66)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - नल-जल योजना का संधारण एवं मरम्मत (24)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी. एच.ई.) - हैंडपंप का संधारण एवं मरम्मत (25)
बैगा सेटलमेंट (72)
अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जाति सघन बस्ती) विकास योजना (57)
अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जनजाति सघन बस्तीस विकास योजना (58)
अजा-अजजा विभाग - अनुसूचित जन जाति विशेष केन्द्रींय सहायता योजना (59)
स्वास्थ्य विभाग -सामुदायिक / उप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण (40)
स्वास्थ्य विभाग -अस्पदताल और ओषधालयों के भवन निर्माण (67)
स्वास्थ्य विभाग - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की राशि (30)
स्वास्थ्य विभाग -विर्निमित तकनीक के साथ उपस्वा्स्थ्य केंद्र निर्माण की राशि (41)
स्वास्थ्य विभाग -उप स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्रीवॉल निर्माण की राशि (42)
दुग्ध संग्रहण केंद्र (79)
मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना (103)
पशु चिकित्साग विभाग- पशु चिकित्साउलय एवं औषधालय निर्माण (37)
निराश्रित निधि (78)
सहकारिता विभाग- गोदाम निर्माण (43)
सहकारिता विभाग- पी.डी.एस. शॉप निर्माण (44)
धर्मस्व विभाग- धर्म-स्थल पुनुरुद्धार (45)
कोर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी फंड (97)
विंध्य विकास प्राधिकरण निधि (69)
मण्डी बोर्ड निधि (70)
मत्स्य विभाग निधि (71)
मत्स्य विभाग - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (75)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (77)
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (83)
आनंद उत्सव (84)
डेयरी विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (86)
एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना (89)
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना (99)
पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना (96)
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (98)
मुख्यमंत्री मदद योजना (102)

के साथ परियोजनाओं में हर वर्ष हर पंचायत में लाखों रुपए आते हैं और जिला पंचायत में हजारों करो जो जिले की ग्राम पंचायतों में खर्च किया जाता है और इन योजनाओं में 40 से 50इ पैसा हजम कर दिया जाता है वहां बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा यही कारण है कि वह घोर अहंकारी इतनी बदतमीजी से बात करते हैं की की सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वालों को जानकारी देने के नाम पर परेशान किया जाता रहता है कुछ गोट भ्रष्ट महा मक्कार कर्मचारी और अधिकारी पैसे की आंख में सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने वालों का हर कदम कदम पर अपमान करते हैं जिसमें इंदौर की पंचायत में ही यह हाल पिछले 20 सालों से लगातार चल रहा है कि वहां बैठे जो कल तक दैनिक वेतन भोगी में आए थे आज वहां पर लेखा अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं और पिछले 20 वर्षों में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए की संपत्तियों के मालिक हैं।

जिला पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रदेश में छापे भी पड़े हैं। और यहां बैठा भारती प्रसारण सेवा का अधिकारी जोग जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है भारी भ्रष्टाचार करके यहीं से अरबों रुपए इकट्ठे करके आराम से कहीं पर भी बाग में जिलों का कलेक्टर बन जाता है और यहां की भ्रष्टाचार कि यह सीख उसको जीवन पर्यंत काम आती रहती है और यह आदत उसके जीवन पर्यंत भ्रष्टाचार की बनी रहती है जो कि वह जिला पंचायत से ही सीखता है।

भाजपा मोदी- 4-5 का विकास, बाकी सबका विनाश

छः महीने के महामारी के पाखंड में भी सारे उद्योग,व्यापार, कृषि सब किये बर्बाद, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला व 5,7 भर आबाद

भाजपा के अटल जी ने 1998 से 2003 तक पहली बार देश की सत्ता संभाली। जिसमें उनके विनिवेश मंत्री अरुण शौरी ने अपने मोटे कमीशन के चलते देश के सारे बड़ी नवरत्न कंपनियों से लेकर अन्य भारत सरकार के उपक्रमों को जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चारों भारतीय तेल कंपनियां भारत पैट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ओएनजीसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर अधिकांश कोयले की खदानें, रेलवे, बीमा कंपनियां, सरकारी बैंक जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर 20 से ज्यादा बैंक आदि के शेयर मार्केट में बेचने के साथ उनमें स्थाई कर्मचारियों को रखने की अपेक्षा बहुत सारे कामों को निजी हाथों में अपने खास पूंजीपति ठेकेदारों को सौंप दिया गया। वहीं भाजपा थी जिसने 2000 में निजी मोबाइल कंपनियों को जिसमें रिलायंस, आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा आदि को लाइसेंस लेकर उसी भारत संचार निगम लिमिटेड के एक्सचेंज का उपयोग करते हुए देश में पहली बार मोबाइल सेवाओं को उतारा गया। परंतु उस समय भी भारत संचार निगम लिमिटेड को मोबाइल चलाने के लिए ना तो आज्ञा दी गई और ना ही उसे मोबाइल के लिए लाइसेंस दिए गए। जबकि किसी भी कंपनी के पास आज तक अपने खुद के एक्सचेंज नहीं हैं। वो सारे एक्सचेंज, जनता के धन से डाली गई, केवल ऑप्टिकल फाइबर लाइने, टावर्स जो भारत संचार निगम लिमिटेड ने हीं 50 साल की मेहनत से उनके इंजीनियरों ने खड़े किए थे। उन सब पर निजी मोबाइल कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए प्रतिदिन की कमाई करती रही और धन बाहर भेजती रही। परंतु भारत संचार को उसकी सेवाओं का उचित मूल्य और किराया तक मोटा कमीशन खाकर नहीं दिया गया। बदले में दूरसंचार नियामक आयोग और दूरसंचार मंत्रालय में बैठे मंत्री से लेकर गिद्ध भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को करोड़ों रुपए प्रतिमाह के टुकड़े डालकर उनका मुंह बंद रखा गया। जबकि अगर समय पर सारी कंपनियां निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनकी सेवाओं को शुल्क का भुगतान कर देती। तो आज भारत संचार निगम लि. का यह हाल नहीं होता उसको किराया जो हजारों करोड़ में था अपने आका पूंजी पतियों को जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी, भारती आदि हैं। उनको पूरी सुविधाएं देकर भारत संचार निगम लि. को डुबोने और लूटने की पूरी छूट दी गई। भारत संचार निगम लिमिटेड की वर्तमान स्थिति सबके सामने है। उसको अपना अस्तित्व बचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और गुजराती भूखे मोदी , अमित शाह सरकार की गिद्ध निगाहें उसके भवनो, भूमियों और संपत्तियों को किराये पर देकर बैचकर उसके पूंजीपति आकाओं का पेट भरने की तैयारी चल रही है। यही हाल बैंकों में जनता के जमा लाखों-करोड़ों की धनराशि मैं वहां बैठे महाप्रबंधक संचालकों आदि ने अपना मोटा कमीशन खाकर इन पूंजी पतियों को जानबूझकर की परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन कर जो लाखों करोड़ का उधार दिया। उसके समय पर पुर्न वापसी ना होने पर ऋणों के विरुद्ध रहन रखी गई संपत्तियों को बेचकर वसूली करने की अपेक्षा इन इन गुजराती धूर्त गिद्धों ने उन ऋणों की माफी देकर बदले में रिजर्व बैंक से उन बैंकों की कर्ज़ों की भरपाई का कुछ हिस्सा पूरा किया।

अब वर्तमान में मोदी सरकार भी यही हाल रेलवे का कर रही है। जहां पर निजी क्षेत्रों में रेलवे की सरकारी पटरियों पर निजी पूंजीपति आकाओं की ट्रेन दौड़ लगाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उन पूंजीपति नीच गिद्धों को इस मोदी सरकार ने सैकड़ों करोड़ के कमीशन के बदले में जो ट्रेन दौड़ाने का जिसमें एक इंदौर उज्जैन से काशी तक महाकाल एक्सप्रेस चलाने की बात कही जा रही है। क्या पटरियों पर उन निजी पूंजीपतियों की खरीदी हुई ट्रेन डिब्बे चलेंगे या ट्रेन उसका इंजन डब्बे भी रेलवे के ही हैं। पर उसकी कमाई अपने पूंजीपति आकाओं को दिलवाई जाएगी। मोटा कमीशन रेलवे मंत्री वित्त मंत्री गृहमंत्री प्रधानमंत्री का हिस्सा विदेशों में जमा होगा जो सब लेंगे। जबकि ट्रेन को इंजन को दौड़ाने से लेकर हर बोगी के कंपार्टमेंट में टीटीइ से लेकर सभी कर्मचारी इंजीनियर एग्जामिनर सब रेलवे के ही होंगे। परंतु उसकी आय उसके पूंजीपति बापों को पहुंचेगी। यह पूंजीपति अपनी ट्रेन को सबसे तेज दौड़ाने, बिना कहीं रुके क़िसी रुकावट और परेशानी के गंतव्य से लेकर चलेगा और गंतव्य तक पहुंच समय पर पहुंच आएगा। इस प्रकार की नि?जी ट्रेनें भारत में चलेंगी। तो वह पूरा रेलवे की अधोसंरचना को खोखला कर देंगी। बदले में मोटी कमाई पूंजीपति ले जाएगा। मोदी अमित शाह यह दोनों गुजराती भूखे भेड़िए पूरे देश की हर शासकीय परिसंपत्तियों को बेचकर गिरवी करके लूट कर खाने में लगे हुए हैं। जिसमें संचार, बैंक, बीमा, तेल कंपनियां, धातु कंपनियां, जिसमें स्टील अथॉरिटी, ताम्र, एलुमिनियम, जिंक, अभ्रक, अन्य धातुओं की जिसमें यूरेनियम तक है। देश की हजारों खदानों से अयस्क निकालकर परिशोधन करके बिक्री करने वाली कंपनियां भी अपने पूंजीपति आकाओं को देकर इस देश का विधाता बना देगा, कर रही है। जितना लूट सके तो लूट अंत काल पछतायेगा सत्ता की गद्दी जाएगी छूट।

यदि आप सच्चे भारतीय हैं, तो जोमैटो, स्विग्गी, अमेजॉन, उबेर, फ्लीपकार्ट से कोई भी सामग्री ना मंगवाए

दूसरी तरफ इनके सारे ऐप भी अपने मोबाइलों से बाहर कर दें सच्चे भारतीय राष्ट्रभक्त होने का ठेका केवल पाखंडी मोदी अमित शाह आर एस एस के भागवत के साथ पूरी देश की भेड़िया झुंड पार्टी ने ही नहीं लिया है।

वैसे तो यह चीन के गुलाम हैं। इन्होंने आज तक आप से नहीं बोला की जोमैटो स्विग्गी और उबेर वह भी चीनी कंपनियां है। और इनके ऐप भी बाहर कर दीजिए।

इनसे खाना मंगवाना बंद कर दीजिए।

बेशक इनकी 20% कमीशन हमारे देश के होटलों रेस्टोरेंट ढाबों से वसूल कर 5% डिलेवरी बाय को देकर, 5% यहां भूखेरे कलेक्टर कमिश्नर टीआई निगम कमिश्नर से लेकर स्थानीय नेताओं प्रदेश के मंत्रियों विधायकों मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचता है।

इसी कारण इन हरामखोर जालसाजों ने देश में फैले जोमैटो स्विग्गी उबेर के 1100 नगरों में इस खाद्य आपूर्ति कि घर पहुंच सेवा देने के साथ-साथ हमारे किसानों से सब्जी छीन कर इस महामारी की आड़ में रु.20 किलो का टमाटर रु. 10 किलो का प्याज आलू व अन्य सब्जियां डेढ़ सौ रुपए में 3.5 किलो घर पर पहुंचाने की व्यवस्था इस पाखंड की आड़ में कर दी गई थी.

बेशक सारे डिलीवरी ब्वॉय भारतीय हैं। जिन्हें मात्र 5% कमीशन मिलता है।

5% कमीशन हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे थानों के टीआई निगम के कमिश्नर कलेक्टर आदि को बांट कर 10% कमीशन नेट वह अपने देश को भेज देती है। इन्होंने उबेर स्विग्गी और जोमैटो के ऐप हटाने के लिए नहीं बोला। क्योंकि उनसे भी पहले कमीशन खाया जा चुका है और अभी भी 5इ कमीशन जो लाखों में होता है हर महीने इनको मिलता है।

इसलिए उन्होंने देश के 5 करोड़ से ज्यादा फुटपाथ पर, ठेलो पर, मंडीयों में सब्जी फल फूल वालों को जिनसे देश के 20 करोड़ लोगों का जीवन चलता है।

बेरोजगार कर भूख से मारने का षड़यंत्र रचने के बदले खातों में 15 लाख डालने का वादा कर चुनाव जीतने के 1 साल बाद महामारी की आड़ में हर माह 5 किलो गेहूं व एक किलो दाल देकर मुंह बंद कर पुनः मसीहा बनने का खेल चल रहा है। यह पाखंडी देशभक्त होने का नाटक करने वाले आपको हमें क्या सिखाएंगे? यदि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं।

तो न केवल चीनी माल बल्कि इन चीनी कंपनियों के माध्यम से हमारे देश का कमीशन बटोर कर ले जाने वाली इन कंपनियों के भी खाद्य सामग्री घर पहुंचाने वाले सारे एप हटा दीजिए।

आगे मर्जी आपकी अगर अंधभक्त हैं। तो भी पूछ लीजिये अपने उस चांडाल आका से कि 59+116 एप में इन कमीशनखोरी करने वाले चीनी दल्लों के एप क्यों नहीं है? या उन शत्रुओं के कमीशन में उनका भी हिस्सा खायें बिना पेट नहीं भरता।

किसानों के लिए मोदी सरकार ने बनाये तीन अध्यादेशों से 3 काले कानून

पेज 16 का शेष

परिणामस्वरूप देशभर में कंपनियों का कॉकस तैयार हो जायेगा।

फसल खरीदी में व्यापारी द्वारा धोखा देने पर किसान की सुनवाई मंडी में नहीं होगी बल्कि एस.डी.एम. और कलेक्टर के यहां होगी। कलेक्टर के आदेश की अपील केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के पास होगी और उनके आदेश की अपील केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास होगी। यानि कि जो विवाद प्रदेश में निपट जाता था अब वह दिल्ली में निपटेगा।

इतना ही नहीं इस अध्यादेश ने किसानों के अदालत में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। वर्तमान समय में मंडी में किसान को उचित दाम, उचित तुलवाई, समय पर भुगतान सहित अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं। इन सुविधाओं के बीच राज्य शासन को मंडी टैक्स के रूप में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व भी मिल रहा था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बन रही थीं और किसानों को मंडी में रहने, ठहरने की सुविधा मिल रही थीं। अब निजी मंडी बनने से यह राशि भी नगण्य हो जाएगी। कर्मचारियों का वेतन नहीं बंट पाएगा।

किसानों को आशंका सही ही प्रतीत होती है कि इन अध्यादेशों के माध्यम से केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से छुटकारा पाना चाह रही है, ताकि किसान सरकार से उचित मूल्य की बात ना कर सकें। भाजपा की केन्द्र सरकार इसी बहाने कृषि उपज सहित किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वचन से भी बचना चाह रही है। आगे चलकर सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी भी बंद करेगी और बड़ी कम्पनियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सीधे खाद्यान खरीदेगी और इस तरह बड़े-बड़े व्यापारी और कम्पनियां किसानों के चारों तरफ अपना जाल बिछा लेंगी। एक अन्य अध्यादेश में सरकार बड़े-बड़े कार्पोरेट घरानों के लिये 'कांट्रेक्ट फार्मिंग' का कानून ला रही है। इस कानून में कम्पनियां किसानों से अनुबंध कर उनकी जमीन पर खेती कराएंगी इस तरह छोटे-छोटे किसान अनुबंध के मायाजाल में फंसकर अपने ही खेतों में मजदूर बन जायेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस तरह की खेती के अनुभव कड़वे रहे हैं। अनुबंध के नाम पर किसानों का शोषण किया गया है। गुजरात में तो कंपनियों ने अनुबंध के नाम पर किसानों पर केस दर्ज करवा दिए थे। केन्द्र सरकार ने अपने तीसरे अध्यादेश में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर गेहूँ, चावल, दलहन, और आलू, प्याज के मनमाने भंडारण की छूट दे दी है। अभी तक इन आवश्यक चीजों की कालाबाज़ारी रोकने के लिये भंडारण की सीमा तय थी। अब सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की स्थिति तथा दोगुनी कीमत न होने तक मनमर्ज़ी से स्टॉक रखने का नियम बना दिया है। यह अध्यादेश भी किसानों और आम उपभोक्ताओं की जगह बड़े व्यापारियों का भला करेगा तथा कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। पहले किसान भंडारण कर सकता था, अब कंपनियों को छूट दे दी गई है। इस फैसले से किसानों में आक्रोश है। भविष्य में यह अध्यादेश अत्यावश्यक वस्तु जैसे गेहूँ, चावल, दलहन, आलू, प्याज की किल्लत का कारण बनेगा। निम्न और मध्यमवर्गीय परिवार महंगी वस्तुएं खरीदने को विवश होंगे। जमाखोऱों और कालाबजारियों को खुली छूट मिल जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक दशक पहले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने देश के ऋण-ग्रस्त किसानों का 72 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर किसानों पर मंदी की मार नहीं पड़ने दी थी। मध्यप्रदेश में 2018 में आयी कांग्रेस सरकार ने भी 20 लाख से अधिक लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ किया था। लेकिन बीजेपी के सत्ता हथियाते ही वह ना सिर्फ़ बंद हो गया, बल्कि उसके कुछ नेता तो इसे पाप तक कहने लगे। आज देश के करोड़ों किसान केन्द्र सरकार से उचित समर्थन मूल्य, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, अनुदान के साथ कृषि उपकरण, खाद्य और कम दर पर बिजली और डीजल की मांग कर रहे हैं। यह सब देने की जगह केन्द्र सरकार बिना आम सहमति बनाए, इस काले कानून रूपी तीन अध्यादेशों को लाकर किसानों की कमर तोड़ने पर आमादा है। जिसमें किसान की जगह कंपनियां आत्मनिर्भर बनेंगी और किसानों की उन बड़ी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी।

आज इन अध्यादेशों को लेकर पूरे देश में ग्रामीण इलाक़ों और मंडियों में किसानों और मंडी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मंडियाँ बंद होने से किसानों की उपज भी नहीं बिक पा रही है। कोरोना काल में जब सभी उद्योग धंधे बंद हैं तब कृषि अर्थव्यस्था को सँभालने का काम कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इन तीनों अध्यादेशों का विरोध होना चाहिए।

सवर्णों की धनाढ्यता और श्रेष्ठता का पाखंड ही बर्बादी का कारण

पेज 16 का शेष

और उन गुंडे बदमाशों के बीच अपनी समाज के कुंवारे लड़के लड़कियों उनके माता-पिता और रिश्तेदारों की सारी गोपनीयता को समाज से परे सड़कों के मावली गुंडे बदमाश नेता मंत्रियों के बीच में बिखेरते रहते हैं। इसका पिछले 20 सालों से बारीकी से अध्ययन किया है। लड़के लड़कियों की 30 साल की उम्र के बाद शादी होना अपने आप में ही एक अभिशाप है। क्या रह गया खोखली छिछोरे बाजी उच्च शिक्षा अधिक कमाई केरियर आदि के चक्कर में शारीरिक मानसिक रूप से तो खोखले और खत्म हो चुके होते हैं। यह निष्कर्ष मैंने उन दंपतियों से निकाले जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर शुक्राणु, अंडाणु, डिंबाणु खरीदे और किराए की कोख से बच्चे पैदा करवाए। अगर 30 साल की उम्र में शादी के बाद 14 -15 की उम्र से 30 साल की उम्र तक स्वच्छंद यौन सुख में गर्भनिरोधकों का उपयोग करने से बांझपन स्त्री और पुरुषों में आया। स्वाभाविक था 30 की उम्र के बाद शादी होने के बाद खोखले हो चुके शरीर में कुछ भी नहीं बचा था। धन है तो लाखों रुपए खर्च करके शुक्राणु, अंडाणु और डिंवाणु खरीद और किराए की कोख से बच्चे पैदा कर भी लिए तो जीवन भर अपने कमजोर होने खरीदे हुए शुक्राणु अंडाणु और डिंबाणुओं से पैदा किए बच्चे का यह दुख मानसिक प्रताड़ना देता रहता है। कि वो हमारे तो नहीं। फिर वे कब बड़े होंगे जब आप 60 साल के हो जाएंगे।समाज में साधु संतों को चाहिए कि सबसे पहले उन लड़कियों की उम्र को 1821 की वर्ष में बीच में और लड़कों की 21 से 20 25 के बीच में विवाह को प्रोत्साहित कर कम से कम हर घर में चार पांच बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें अन्यथा ना केवल जैनी माहेश्वरी बामन बनिया सब खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं और मुसलमान साथ में बैठा हुआ है। यह हमारी धनाढ्यता और श्रेष्ठता का पाखंड हमें, हमारे परिवारों को हमारी समाज को और पूरी हिंदू संस्कृति को धरती से मिटा देगा। बेशक मेरे ये कड़वे प्रवचन मानसिक कष्ट देंगे पर मैं चाहता हूं मानसिक कष्ट हो मैं बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगा ना आप मुझे क्षमा करें परंतु मेरे लिखे कड़वे सच को समझें और समाज के उत्थान पर हर कदम हर पल काम करें पाखंड नहीं। अन्यथा यह पाखंड हमारे अंत का कारण बन चुका है।

डरो मत, सावधानी रखो

पेज 16 का शेष

वह आठवीं दसवीं पास लड़के लड़कियां कुछ भी टेस्ट निकाल कर बताते रहते हैं और वहां के मालिक डॉक्टर या अन्य कर्मी मोटे कमीशन व मरीज की हसीयत और सैंपल भेजने वाले डॉक्टरों की इच्छा के आधार पर वह जांच रिपोर्ट नकरात्मक व सकारात्मक जारी करते रहते हैं। ऑखिर भारत की सरकारी व निजी अस्पतालों की इसी प्रकार प्रयोगशालाओं के हाल तो देश की जनता अच्छी तरह से जानती, समझती देखती रही है।

इन सब के बारे में मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से ही 26 मार्च के बाद से लगातार लिख रहा हूं।

दूसरी तरफ जो 4 दवाइयां ऐसे मरीजों को दी जा रही है उसमें हाइड्रो ऑक्सिक्लोरो को इनके बारे में मैंने 28 मार्च को देश और दुनिया को अपनी साइट www.samaymay.com से बताया था कि यह दवाई सबसे ज्यादा लोगों की आंखों पर हृदय लिवर और किडनी पर असर करती है और आदमी को अंधा बनाने से लेकर उसके लीवर किडनी और हृदय को बाधित कर मृत्यु कार्य कर सकती है यह रिपोर्ट उसी का एक हिस्सा है और एलोपैथिक डॉक्टर इनके पास ना तो कोई दवाई है ना कोई परफेक्ट ठोस इलाज जो जिसके मन में आ रहा है वह देख कर अपने-अपने दावे कर लोगों की जान से और मौत से खेल रहा है लाखों रुपए लूटने के बाद में भी लोगों रु. 700 का इंजेक्शन 34000 से लेकर 39000 मरीजों को लगा लगा कर मोटी कमाई करने के साथ सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में मौत का तांडव चल रहा है शासन के पास ना तो डॉक्टर हैं न जांच करने के अधिकारी जो जैसा बोल देता है वहां के डॉक्टर जा मोटा कमीशन मोटी कमाई दिखती है वह भूखे भेड़िए उसकी तरफ चल देते हैं और देश में महामारी का पाखंड कर देश के व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था बच्चों की शिक्षा और जनता को बर्बाद करने में पिछले 6 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जिससे फ्लू, वायरल, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, इनफ्लुएंजा, टीवी, सांस दमा भरना, माता जैसी बीमारियां होती है। हर बदलते हुए मौसम में आज से नहीं हजारों साल से हो रहे हैं। और उससे 8000 आदमी प्रतिदिन हमारे भारत में सन 2000 से अभी तक मरते चले आ रहे हैं। जबकि भारत में सन् 1900 से औद्योगिक क्रांति व कपड़ा मीलों, की शुरूवात से ही यक्ष्मा या टीबी के रोगीयों की संख्या भारत में लाखों में दुनिया में सबसे ज्यादा रही है।

कुछ भी नया नहीं होने के उपरांत भी केवल पूंजी पतियों के इशारे पर सारे फुटकर व्यवसाय बाजारों मंडियों को खत्म करने, 50 अरब करोड़ के बाजार पर कब्जा जमाने, देश के 20करोड़ लोगों को बेरोजगार करने, सारी शिक्षा को ऑनलाइन करके, भारतीय धर्म व संस्कृति को खत्म करने बच्चों को अपनी तरह से पढ़ाने अपने रंग, ढंग में ढालने, विद्यार्थियों को शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बनाने, फिर लाखों करोड़ की दवायें बेंचने, गूगल द्वारा धीरे धीरे अमेरिका से पढ़ाने, शिक्षा के व्यवसाय को जो अकेले देश में ही 50 लाख करोड़ रूप से ज्यादा का है, जिसमें 80लाख शिक्षक बेरोजगार होंगे, चौपट करने, उस पर कब्जा जमाने बच्चों को बचपन से ही मोबाइलों की लत डालकर उनसे ऑनलाइन शॉपिंग मॉल वालमार्ट, ईजीशाप, अमेजॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जिओ मार्ट, रिलायंस रिटेल, बिग बाजार आदि से खरीदी करवाने के षड्यंत्र का और देश व दुनिया को गुलाम बनाने के षड्यंत्र का खेल है। यह महामारी का पाखंड है, जिसमें देश की सरकारें विदेशी पूंजी पतियों की कठपुतलियां बन नाच रही हैं। जनता और देश की सरकार को जागना ही होगा।

साप्ताहिक समय माया

सवर्णों की धनाढ्यता और श्रेष्ठता का पाखंड ही बर्बादी का कारण

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाकी परिवार का अपने माल बेचने का षड्यंत्र जो उन्होंने पिछले 40 सालों में चलाया पूर्णता सफल रहा क्योंकि एक संयुक्त 15-20 सदस्यों के परिवार में एक टीवी फोन एक वाशिंग मशीन एक ऐसी काम क्यों चलाया जाए। जबकि नाम दिया गया छोटा परिवार सुखी परिवार यथार्थ में छोटा परिवार दुखी परिवार में बदल गया। ताई ताऊ काका काकी दादा दादी, संयुक्त घर में रहते थे। घर में मम्मी पापा नहीं भी होते थे। या उनमें विवाद हो जाने पर उनको समझाने संभालने वाले दोनों के मनमुटाव को दूर कर सब को खुश रखते और रहते थे। उनकी छत्रछाया में वो मासूम कोमल बच्चे उनसे लिपटे रहते हैं। संयुक्त परिवार की छत्रछाया में घर के बच्चे उनका हाथ पकड़ के हंसते खेलते कब बड़े हो जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था। संयुक्त परिवार में आर्थिक सामाजिक मानसिक जो सबका एक दूसरे को सहयोग मिलता था वह अतुलनीय अविस्मरणीय होता है आज एक छोटे परिवारों में एकाकी बच्चे संगी साथियों ने माता-पिता के साथ दादी दादा काका काकी ताऊ ताई बुआ भतीजा का सहयोग न मिलने छोटी-छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं उन्हें कोई समझने सुनने वाला नहीं।

जितने छोटे परिवार होंगे उतना ज्यादा उनका माल बिकेगा इस धुर स्पष्ट षड्यंत्र में हम आधुनिकता की अज्ञानता में अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। अब हर रिश्ता हम धन से तोलने लगे। अब हमें अपने भी अपने धन के आगे छोटे और त्याज्य लगने लगे। संयुक्त परिवार में जो जैसा है वह वैसा है और घर में उसका उस जैसा मान सम्मान के साथ उपयोग भी है। अनपढ़ है। तो भी और ज्ञानी है तो भी सबका धन सबके लिए कोई बेरोजगार है। या किसी के पास रोजगार है। संयुक्त परिवार में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ा है तो भी सब खुश हैं ज्यादा है तो भी कोई फर्क नहीं सब एक साथ मिलकर एक दूसरे का सुख दुख दर्द बांटते थे। हर छोटा त्योहार मनाने का भी आनंद होता था। पर अब छोटे परिवारों में थोड़ी सी आर्थिक सामाजिक मानसिक परेशानी बेरोजगारी तनाव भुखमरी और मौत का कारण बन जाती है। सबसे ज्यादा आत्महत्या सवर्णों में उच्च वर्ग में ही ज्यादा हो रही है। पर कोई कारणों में जाना जानना नहीं चाहता। शादी ब्याह संबंध आदि में भी इस प्रकार की छिछोरे बाजी मंचों पर अपनी पहचान बताना। प्रदर्शनी लगाना। मंचो पर खड़े होकर अपने शादी की गुहार लगाना। और इन कामों के लिए हर समाज में दल्लों की बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है। जो ऐसे ही लोगों से हजारों रुपए वसूलने के बाद अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े गुंडे बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के नेता और मंत्रियों को बुला कर खड़ा कर लेती है।

(शेष पेज 15 पर)

चारों तरफ़ पूजींपतियों की सरकारी लूट का षड़यंत्र

डरो मत, सावधानी रखो

महामारी के पाखंड की आड़ में सर्दी खांसी जुकाम की साधारण बीमारी में जानबूझकर करोना बता कर, जबकि उसका ना तो वायरस, ना सरकारी व निजी अस्पतालों में, ना अच्छी प्रयोगशाला हैं, ना जांच करने के अच्छे उपकरण, ना मशीनें, ना स्टॉफ, न ही टेस्टिंग किट, न ही कोई ठोस व पक्की दवायें है। फिर भी चारों तरफ हर तरह की लूट का पाखंड क्यों? सारी मौतें अस्पतालों में ही हो रहीं। अगर महामारी है, तो 25 लाख भिखारी, 20 करोड़ गरीब मजदूर, 2 करोड़ सफाईकर्मी क्यों नहीं सड़कों पर घरों में उद्योगों में मरे। पिछले 22 मार्च से लगातार इस महामारी के पाखंड की सच्चाई यों को हर कदम पर जनता को सावधान रहने जागरूक करने और उसको स्वस्थ रहकर अपने जीवन को अपने परिवार के जीवन को बचाने की सलाह देता रहा हूं। अपने वीडियो के माध्यम से ही जितने मैंने वीडियो भेजे। इन सब कुछ सच्चाईयों की पुष्टि अब 6 महीने में लगभग देश व दुनिया के हर कोने में हो चुकी है। सारा पाखंड बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने ऑनलाइन व्यवसाय और शॉपिंग मालस वालों को चलाने के व्यवसाय का हिस्सा होने के साथ-साथ अमेरिकी जालसाज दवा बनाने, उपकरण बनाने, इंजेक्शन, वैक्सीन बनाने वाली जालसाज, पूंजीपति डकैतों की कंपनियों का व्यवसाय संवर्धन करने वाली इस संस्था का कार्य ही जनता के मन में बीमारी का भय फैला भारी धन मीडिया व डॉक्टरों पर खर्च करके माध्यम से डब्ल्यूएचओ की दानदाता कं की मोटी लाखों करोड़ की कमाई के लिये इस जैसी हरामखोर पाखंडी जालसाज संस्था 70 साल का इतिहास इन्हीं पाखंडों और जालसजियों से भरा है। पिछले 50 सालों में, पहले इन कंपनियों ने खेती में डीडीटी का प्रयोग किया डीडीटी के प्रयोग से, पोलिओ फैला फिर उसके इलाज के नाम उसकें हजारों करोड़ के टीके बेंचे।

एड्स के नाम पर कंडोम का लाखों करोड़ का स्थायी कमाई का कारोबार कर रही, 10 पैसे की गर्भनिरोधक गोलियां, रु 20 से रु 50/- तक, अब गर्भ जांचने की किट भी बाजार में उपलब्ध हैं। 10-20 पैसे का कंडोम रु10से खुशबु वाले रु.100/- तक बहुराष्ट्रीय कं. के, पीलिया की बीमारी के नाम पर हेपेटाइटिस ए से लेकर जेड तक के टीके, स्वाइन फ्लू डेंगू बर्ड फ्लू के टीके,सभी बिल गेट की कं. के

कोरोना के पाखंड की आड़ में सर्दी खांसी जुकाम की साधारण बीमारी में जानबूझकर करोना बता बता कर उसका ना तो वायरस है ना सरकारी व निजी अस्पतालों में, ना अच्छी प्रयोगशाला हैं, ना जांच करने के अच्छे उपकरण, ना मशीनें, ना स्टॉफ, न ही पास टेस्टिंग किट, न ही कोई ठोस व पक्की दवायें है। फिर भी चारों तरफ दहशत के कारोबार से हर तरह की लूट का पाखंड क्यों?

जो नकारात्मक को सकारात्मकता की इस महामारी की रिपोर्ट जारी करते हैं। उन जांच करने वालों के पास न्यूनतम एमएससी पैथोलॉजी या एमडी पैथोलॉजी होना आवश्यक है। जबकि स्टाफ की भर्ती 1990 से सरकारी कार्यालयों में बंद है और निजी का तो भगवान ही मालिक है

(शेष पेज 15 पर)

कृषि को बहुराष्ट्रीय कंपनी के हवाले करने

किसानों के लिए मोदी सरकार ने बनाये तीन अध्यादेशों से 3 काले कानून

भारत में कृषि सुधार के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीन अध्यादेशों का पूरे देश में विरोध हो रहा है। किसानों का कहना है कि पहले अध्यादेश में कृषि उपज मंडियों के बंद होने से किसानों का शोषण शुरू हो जाएगा। दूसरे अध्यादेश में गेहूँ, चावल, दलहन और आलू, प्याज के भंडारण की छूट देने से कालाबाज़ारी शुरू हो जाएगी। अंततः मध्यम और निम्न वर्ग जमाखोरी के कारण मूल्य वृद्धि का शिकार बनेगा। तीसरे अध्यादेश में अनुबंधित कृषि का प्रावधान है। ऐसा होने पर छोटे किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएंगे।

मोदी सरकार द्वारा सुधार के नाम पर लाए जा रहे ये तीनों अध्यादेश वास्तव में किसान, छोटे व मध्यम व्यापारी और उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत हैं। हर राज्य के किसान संगठन, व्यापारी संघ और कर्मचारी यूनियन इन अध्यादेशों को काला कानून बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि उचित मूल्य और बेहतर बाजार के नाम पर केन्द्र सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में किसानों की किस्मत सौंपने जा रही है। जो किसानों का पोषण नहीं बल्कि शोषण करेंगे। मैं भी इस आशंका से सहमत हूँ।

जब देश में लॉकडाउन था और करोड़ों लोग कोरोना की दहशत में थे तब किसानों का भला करने की जगह बड़ी-बड़ी कम्पनियों का भला करने के लिये 'कोरोना के संकट काल में' केन्द्र सरकार ने हमेशा की तरह अध्यादेश का सहारा लिया और बिना किसानों से संवाद और संसद में चर्चा कराए किसानों पर काला कानून लागू कर दिया। राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार की भी अनदेखी की है।

इस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जनता की 'आपदा' में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 'अवसर' ढूँढ लिया!

हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के दस करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी मेहनत से हरित क्रांति के सहारे देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकारों ने

महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कृषि विकास में अनेक दूरगामी निर्णय लिए थे, जो उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने में सहायक रहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया ताकि बाजार में जीवन उपयोगी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके।

खाद्यान्न की कमी से जूझते देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agriculture Costs and Prices) गठित किया जिसकी अनुशंसाओं पर किसानों को उनकी लागत के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिए जाने के प्रावधान किए गए।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की परम्परागत खेती को अनेक कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ कर हरित क्रांति में बदल दिया। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। सिर्फ तीन दशक में किसानों ने शासकीय सुविधाओं के सहारे खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बना दिया था।

70 के दशक में किसानों को व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम विभिन्न प्रदेशों में लागू किए गए। इस कानून के तहत किसानों के लिए मंडी समितियां स्थापित की गईं। मंडी कानून ने किसानों को संरक्षण देते हुए उन्हें अपनी फसल के उचित दाम दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। मंडी अधिनियम में किसानों के प्रतिनिधि मंडी समिति के अध्यक्ष होते हैं और निर्वाचित संचालकों में किसानों के वोटों की सीधी भागीदारी होती है। व्यापारियों और हम्मालों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल किए गए। इन सभी को मिलकर हर समस्या का समाधान निकालने के लिए कानूनी तौर पर अधिकार सम्पन्न किया गया है। मध्यप्रदेश में यह कानून 1973 से लागू हो गया था। कृषि उपज मंडी अधिनियम को अब इस अध्यादेश के माध्यम से नगण्य किया जा रहा है, जबकि हमारे देश के संविधान में कृषि को संविधान के अनुच्छेद 246 में वर्णित 7वीं अनुसूची में राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। पिछले 50 सालों में कृषि उपज मंडियां किसानों की आशाओं का केन्द्र बन गई हैं, जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोली लगाकर फसलों की बिक्री होती है। वाजिब दाम मिलने पर ही किसान अपनी फसल व्यापारी को बेचता है। व्यापारी उसी दिन भुगतान भी करता है। विलंब होने पर व्यापारी किसान को एक प्रतिशत की दर से 5 दिनों तक ब्याज देता था और 5 दिन से ज्यादा देरी होने पर उसके बाद 5% ब्याज की दर से भुगतान किया जाता है। नाबार्ड की रिपोर्ट बताती है कि देश में दस करोड़ से अधिक किसान है, जिनमें से आधे से अधिक कर्ज में डूबे हैं। ऐसे में अब नए अध्यादेश से शासकीय कृषि उपज मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और व्यापारी भी अनियंत्रित हो जाएंगे। निजी मंडियां खुल जाएंगी और किसान दर-दर भटकता फिरेगा। किसानों का आरोप है कि आटा, मैदा सहित अन्य उत्पाद बनाने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां मनमानी कीमतों पर किसानों को फसल बेचने मजबूर करेंगी। (शेष पेज 15 पर)

www.samaymaya.com की साइट से समाचार पत्र की पीडीएफ डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को भेज सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256-37958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 94251-25569, 94795-35569